राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष-48 ■ अंक-01 ■ अप्रैल 2026 ■ ₹10 ■ पृष्ठ-36

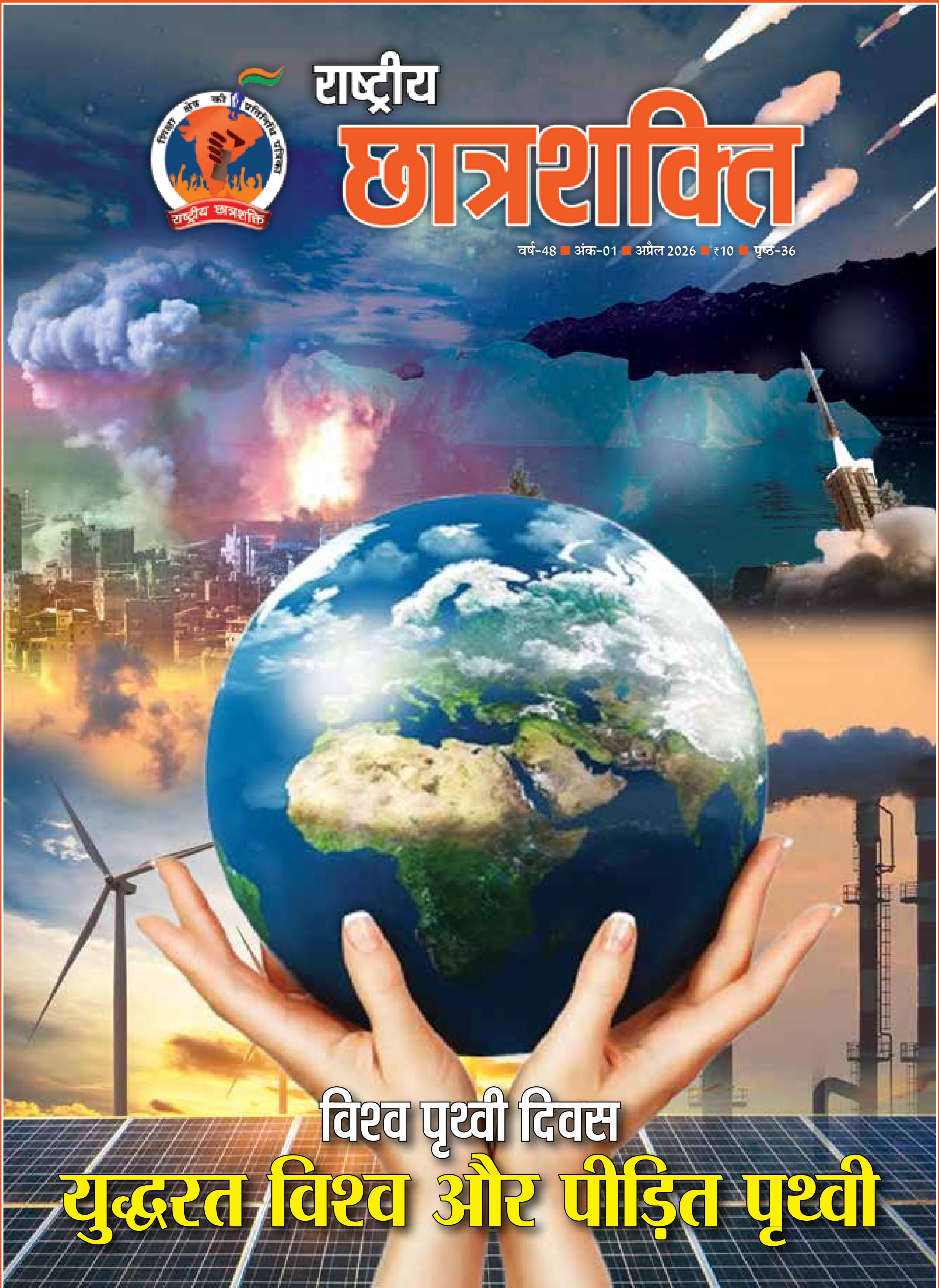

विश्व पृथ्वी दिवस

युद्धरत विश्व और पीड़ित पृथ्वी

जम्मू : राष्ट्रीय एकता यात्रा–2026 के अंतर्गत लद्दाख से आए प्रतिनिधियों के सम्मान में जम्मू महानगर में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह।

कुल्लू : राष्ट्रीय एकता यात्रा के प्रतिनिधियों द्वारा बौद्ध मठ, शाढाबाई का भ्रमण।

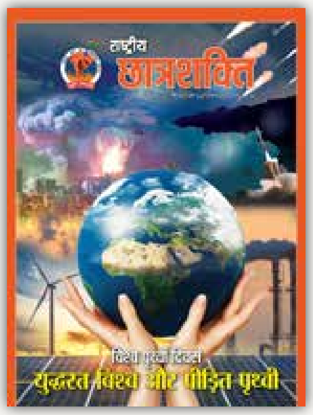

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष-48, अंक-01
अप्रैल 2026

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक मण्डल
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

05 **वैश्विक परिस्थितियां एवं पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका**
वैश्विक और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक...

संपादकीय	04
CULTURE, CONFLICT AND CLIMATE UNMASKING THE BIAS IN ENVIRONMENTAL DISCOURSE	08
अभाविप ने सरकार पर लगाया भाषाई तुष्टिकरण का आरोप	11
Pakistan-Afghanistan conflict : An Overview	12
गुरु दक्षिणा	15
सामाजिक-सांस्कृतिक एकता का दर्शन	16
जनजातीय गौरव की विरोधी है ममता सरकार : अभाविप	17
व्यक्ति एक-आयाम अनेक	18
National Legal Conclave Highlights Vision of 'Viksit Bharat–2047'	20
राष्ट्रभक्ति की अमर पुकार	22
रचनात्मकता को मिले पंख	25
उत्तर-पूर्व में कृषि के भविष्य पर मंथन	26
नवाचार और उद्यमिता पर मंथन	28
A Grand Celebration of Young Filmmakers and Cinematic Innovation	29
नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता का भव्य प्रदर्शन	30
अभाविप के विरोध के बाद लिया गया पाठ्यक्रम बदलने का निर्णय	31
जीवंत हुए 'प्रिय केलकर'	32
ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्लुएंस-2026	33
महापुरुषों का अपमान करने वालों के विरुद्ध होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई : अभाविप	34

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

यह अंक आपके हाथों में पहुंचने से पहले ही देश से माओवाद के हिंसक ढ़ांचे के ढ़ह जाने का समाचार आप तक पहुंच चुका होगा। दशकों तक आतंक का पर्याय बने माओवादी मध्यवर्ती भारत में हिंसा के बल पर जनजीवन को बंधक बनाने में सफल रहे। इच्छाशक्ति के अभाव और निहित स्वार्थों के चलते राजनैतिक नेतृत्व ने समस्या को प्रबंधित करने के तात्कालिक उपाय तो किए, किन्तु उस पर निर्णायक प्रहार करने का साहस नहीं दिखाया। परिणामस्वरूप, हजारों निर्दोष लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ा, लाखों लोगों को आतंक के साए में जीने को अभिशप्त होना पड़ा, गत तीन पीढ़ियों में करोड़ों लोग विकास योजनाओं से अछूते रह गए।

गत 25 वर्षों के संग्रहीत आंकड़ों को देखें तो 5,679 घटनाओं में 4,138 निर्दोष नागरिक, 2,723 सुरक्षा बलों के जवान तथा 5,063 माओवादियों सहित कुल 12,176 लोगों की मृत्यु हुई। पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ यह हिंसक आंदोलन विदेशी धन और हथियार के बल पर फैलता गया। मध्यवर्ती भारत में इसकी जड़ें गहराई से जम गईं क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां उनके अनुकूल थीं। सरकारों की उदासीनता के कारण उनकी गतिविधियों का व्याप बढ़ता गया और वह पशुपति से तिरुपति तक लाल गलियारा बना कर भारत को तोड़ने के षड्यंत्र बुनते रहे।

आज जब यह परिस्थिति बदली है और सरकार द्वारा माओवादी हिंसा पर निर्णायक प्रहार किया गया है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के लिए यह एक सपने के पूरा होने जैसा है। भारत को तोड़ने के इस अभियान का प्रतिकार करते हुए परिषद के अनेकानेक कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है। तिरंगे की रक्षा में इन बर्बर आतंकियों से निहत्थे ही भिड़ जाने वाले कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान से समाज के सामने एक आदर्श रखा। इन बलिदानों की एक शृंखला चली और दशकों बाद आज यह अवसर आया है, जब माओवाद के विरुद्ध इस निर्णायक जीत को उन समस्त बलिदानियों को समर्पित कर सकते हैं।

माओवाद प्रभावित क्षेत्र के निवासी निस्संदेह आज चैन की सांस ले रहे हैं, किन्तु विगत दशकों में उन्होंने लाल आतंक के चलते बड़ी कीमत चुकाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहने का दंश उन्होंने झेला है।

माओवाद प्रभावित क्षेत्र के निवासी निस्संदेह आज चैन की सांस ले रहे हैं, किन्तु विगत दशकों में उन्होंने लाल आतंक के चलते बड़ी कीमत चुकाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहने का दंश उन्होंने झेला है। विकास की यात्रा में वह चाह कर भी शामिल नहीं हो सके। शायद ही कोई परिवार बचा होगा, जिसे जान-माल का नुकसान न उठाना पड़ा हो। निरंतर भय के साए में जीने को वह अभिशप्त रहे हैं। इसलिये केवल आतंक की समाप्ति ही उनके लिए खुशहाली नहीं ला सकेगी। उनके दैनंदिन जीवन के प्रश्नों को संबोधित करना होगा। अभावों को पाटना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, उनके मन पर लगे घावों का उपचार करना होगा। अभाविप अपने 'अनुभूति' प्रकल्प के माध्यम से पहले ही इसकी पहल कर चुकी है। इसे और व्यापक रूप से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ले जाने की जिम्मेदारी अभाविप कार्यकर्ता उठायेंगे ही, साथ ही सब समाज को साथ लेकर इसके लिए सामूहिक प्रयास भी करने आवश्यक होंगे, जो भारत का स्वभाव ही है।

पश्चिम एशिया में शुरू हुआ संघर्ष फैलता जा रहा है और इसके वैश्विक प्रभाव अब सामने आने लगे हैं। जिन देशों का इस युद्ध से दूर का नाता भी नहीं है, वह भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। एक ओर पेट्रोलियम के दामों में असामान्य वृद्धि तो दूसरी ओर उसका उद्योग जगत और कृषि पर पड़ने वाला प्रभाव सारी दुनिया को चिंतित कर रहा है। पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का आकलन किया जाना अभी बाकी है। इस परिस्थिति में भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की संकल्पना तथा 'विश्वमित्र' की भूमिका ही एकमात्र आशा की किरण है।

आपका
संपादक

वैश्विक परिस्थितियां एवं पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका

■ डा. मयंक पांडेय

वैश्विक और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के मध्य सामंजस्य कैसे बनाया जाए? इसके लिए 1987 में ब्रंडट्लैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 'Our Common Future' में सतत विकास की अवधारणा को पहली बार दुनिया के सामने रखा। सतत विकास का अर्थ ऐसे विकास से है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान उपभोग इस प्रकार होना चाहिए, जिससे भविष्य की पीढ़ियां इनके उपभोग से वंचित ना रह जाएं।

सतत विकास के तीन आधार-स्तंभ हैं-पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों को विश्व के सामने रखा, जिन्हें सतत विकास प्राप्त करने का माध्यम माना गया। सतत विकास लक्ष्यों की समय-सीमा 2030 में समाप्त हो रही है और भारत सहित विश्व के कई देश इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही, विश्व के अनेक छोटे-बड़े सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठन और प्रतिष्ठान भी विभिन्न वित्तीय सहायता के माध्यम से इस लक्ष्य-प्राप्ति में अपना-अपना योगदान दे रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण तिथियां घोषित की गई हैं, जिन पर प्रतिवर्ष किसी एक थीम पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण तिथि है 22 अप्रैल, जिसे 'विश्व पृथ्वी दिवस' के रूप में 1970 से मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष (2026) विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है 'हमारी ऊर्जा-हमारा ग्रह'। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता संरक्षण, मानव-जनित प्राकृतिक आपदाओं जैसे वैश्विक संकटों से निपटने के लिए अनेक संधियों एवं समझौतों पर विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही अनेक देश अपने-अपने सामर्थ्य एवं इच्छाशक्ति के अनुसार इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं।

भारतवर्ष में पर्यावरण संरक्षण यहां की संस्कृति का अभिन्न अंग है और ऐतिहासिक काल से ही व्यक्ति/

व्यक्तियों के समूह जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर को बचाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। आज भी अपने देश में अनेक व्यक्ति (जैसे सुभाष पालेकर, तुलसी गौड़ा, हिम्मत राम शंभु, कुशल कुंवर शर्मा, विजय जरधारी आदि), समूह और संगठन (जैसे विकासार्थ विद्यार्थी, लोक भारती, ग्राम विकास योजना, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि आदि) देश के अलग-अलग हिस्सों में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के अद्भुत समन्वय से सतत विकास के तीनों स्तंभों को संजोने-बचाने में जुटे हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

सतही तौर पर देखने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत आदर्श स्थिति लगती है। लेकिन गहनता से पड़ताल करने और हालिया भू-राजनीतिक परिदृश्यों को देखने से पता चलता है कि इन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के क्रियान्वयन में दोहरी नीति अपनायी जा रही है। विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियां अपने हितों को साधने के लिए आवश्यकतानुसार जहां एक ओर विकासशील देशों पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अनावश्यक दबाव बनाती हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुविधानुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों से स्वयं को अलग कर लेती हैं। यही नहीं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विगत लंबे समय से सशस्त्र संघर्षों में लिप्त हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के गतिरोधों और संघर्षों के विपरीत एवं गंभीर प्रभाव सतत विकास के तीनों आधार-स्तंभों; पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे हैं, जिसके अपने दीर्घकालिक परिणाम होंगे। ऐसे में क्या यह प्रश्न नहीं उठता कि पर्यावरण संरक्षण केवल विकासशील देशों का ही कर्तव्य है?

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ध्रुवीय ताकतों के रूप में उभरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का पर्यावरण के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? जीवाश्म ईंधन और खनिज पदार्थों पर एकाधिकार का प्रयास पृथ्वी पर उपलब्ध जीवन के लिए कहां तक लाभदायक सिद्ध होगा? यह प्रश्न तब और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं, जब एक ओर स्टॉकहोम कांफ्रेंस से लेकर अब तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह विकसित देश प्रकृति के जैविक और अजैविक तत्वों को बचाने के वादे करते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, जब जमीनी स्तर पर कार्य करने का समय आता है तो ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण समझौतों से अपना नाम वापस लेकर दूरी बना लेते हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास : भारत बनाम विकसित देश

2023 के सकल कार्बन उत्सर्जन के आंकड़ों पर नजर डालें तो सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में चीन (34 प्रतिशत) और संयुक्त राज्य अमेरिका (12 प्रतिशत) के बाद भारत (7.5 प्रतिशत) तीसरे स्थान पर आता है। हालांकि, भारत का यह विश्वास है कि सकल कार्बन उत्सर्जन के स्थान पर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (Per Capita Emissions) अधिक विश्वसनीय और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.9 टन है जो विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। कौंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में औसत आय वाले व्यक्ति का कार्बन उत्सर्जन भारत, ब्राजील और अन्य विकासशील देशों के सबसे धनी दस प्रतिशत लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2025 की दूसरी छमाही में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और पूरे वर्ष में केवल 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो दो दशक से अधिक समय में सबसे धीमी दर है।

भारत में स्वच्छ ऊर्जा की रिकॉर्ड वृद्धि और बिजली की कम मांग के कारण विद्युत क्षेत्र में उत्सर्जन में 3.8 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2025 में नई स्वच्छ ऊर्जा क्षमता से प्रति वर्ष रिकॉर्ड 90 टेरावॉट घंटे (TWh) बिजली उत्पादन बढ़ेगा, जो 2024 में बने पिछले रिकॉर्ड का दोगुना है। भारत ने जून 2025 में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी कुल विद्युत स्थापित क्षमता का पचास प्रतिशत हासिल कर लिया, जो पेरिस समझौते के लिए निर्धारित राष्ट्रीय योगदान (एनडीसी) के तहत 2030 के लक्ष्य से पांच वर्ष से पहले है।

भारत ने अगस्त 2025 में गैर-जीवाश्म विद्युत स्थापित क्षमता का 250 गीगावॉट का आंकड़ा पार कर लिया। नवंबर 2025 तक कुल गैर-जीवाश्म विद्युत स्थापित क्षमता 262.74 गीगावॉट तक पहुंच गई है, जो देश की कुल विद्युत स्थापित क्षमता (509.64 गीगावॉट)

का 51.5 प्रतिशत है। 2025 में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 44.51 गीगावॉट तक पहुंची, जो 2024 की तुलना में लगभग दोगुनी है। भारत के ऊर्जा क्षेत्र की इस प्रगति में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों (जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा) का प्रमुख योगदान है। जुलाई 2025 में भारत ने बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की अब तक की सबसे अधिक हिस्सेदारी हासिल की-उस दिन नवीकरणीय ऊर्जा ने देश की कुल 203 गीगावाट बिजली मांग का 51.5 प्रतिशत पूरा किया। इससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा। यह आंकड़े और उदाहरण भारत द्वारा समग्र पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता को दिखाते हैं

दूसरी ओर, विकसित देशों द्वारा अपनायी जाने वाली जीवनशैली, जीवाश्म ईंधन पर अत्यंत निर्भरता और प्राकृतिक ह्रास के लिए विकासशील देशों पर दोषारोपण, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार के व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। परिणामस्वरूप वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, जिसे आज जलवायु परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना और अत्यधिक मौसमीय घटनाएं इसी के उदाहरण हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की निम्न गतिविधियां पर्यावरण संरक्षण में गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रही हैं-

अत्यधिक उपभोगवाद की संस्कृति : विकसित देशों में आमतौर पर उपभोग का स्तर बहुत अधिक होता है, जिससे पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है। परिणामस्वरूप अधिकांश विकासशील देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है।

जीवाश्म ईंधन पर निरंतर निर्भरता : जलवायु प्रतिबद्धताओं के बावजूद, कई विकसित देश अभी भी कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर हैं।

विकासशील देशों को प्रदूषणकारी उद्योग एवं प्रदूषकों का हस्तांतरण : कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को विकासशील देशों में स्थानांतरित कर दिया है। साथ ही, वह अपने यहां निकलने वाले खतरनाक ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों को अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका आदि के विकासशील देशों में डलवा देते हैं, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं।

पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं का कमजोर कार्यान्वयन : विकसित देश महत्वाकांक्षी जलवायु प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन धीमा हो सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं-उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने में देरी, जलवायु कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन न देना और पर्यावरण संरक्षण नीतियों पर राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन का सीधा प्रभाव।

ऐतिहासिक उत्तरदायित्व : प्रथम औद्योगिक क्रांति के बाद से ही ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा विकसित राष्ट्रों से आता रहा है ।

निष्कर्ष

पश्चिमी देशों द्वारा औद्योगिकीकरण और उपभोक्तावाद के कारण पर्यावरण का अत्यधिक दोहन हुआ है, परिणामस्वरूप आज विश्व जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है। इसके विपरीत भारत की सांस्कृतिक परंपरा और जीवन-शैली प्रकृति के साथ संतुलन और संरक्षण की भावना पर आधारित रही हैं। वैश्विक समस्याओं का समाधान केवल किसी एक देश द्वारा संभव नहीं है। केवल वैश्विक सहयोग के माध्यम से ही पर्यावरणीय संकट से प्रभावी रूप से निपटा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि-

- विकसित देश अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करें
- स्वच्छ तकनीक का विकास और साझा करें
- विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करें

पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक सहयोग अत्यंत आवश्यक है जिसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं-तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहायता, ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान एवं संयुक्त अनुसंधान और नवाचार।

आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व भारत के पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रेरणा ले और विकास के साथ-साथ प्रकृति के संरक्षण को भी प्राथमिकता दे। यदि पश्चिमी जगत सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों को सही मायने में अपनाता है, तो ही पृथ्वी को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध बनाया जा सकता है। ■

(लेखक, पीजीडीएवी (सांध्य), दिल्ली में सहायक प्राध्यापक हैं।)

CULTURE, CONFLICT AND CLIMATE

UNMASKING THE BIAS IN ENVIRONMENTAL DISCOURSE

■ DIGANTA CHAKRABORTY

Bharat is not only a country; it is a living civilisation. Bhartiya culture teaches that the environment is a crucial part of this civilisation. This is why our Sanatana culture reveres trees as divine. Although some attempt to portray this as prejudice, it was, in fact, a system designed to protect the environment. Moreover, this is the only nation whose scriptures proclaim, 'Prakriti Panchabhutani Grahaloka Samasthita,' which means that nature, composed of the five elements, is established throughout the planetary worlds.

But often we see how some propaganda is created just to portray that Hindu Dharma is against the environment. Every year, as autumn settles over Bharat and our homes prepare to welcome light over darkness, another ritual unfolds alongside the celebrations of Diwali, a ritual of condemnation. Television debates flare up, op-eds warn of ecological collapse, and social media fills with urgent appeals to 'save the environment' from firecrackers. We see celebrities across the world suddenly becoming environmental specialists; they express great concern over Diwali firecrackers, though they use them at their personal events.The festival, rooted in centuries of civilizational memory, is increasingly portrayed not as a cultural expression, but as an environmental liability.

Yet, in the same global moment, skies over conflict zones burn far brighter and far longer than any Diwali night. Missiles tear through landscapes, oil depots erupt into infernos, forests are reduced to ash, and toxic plumes spread across borders without passports. The environmental cost of war unfolds not for a night, but for months and years And strangely, the outrage fades into near silence. This silence is not accidental. It reveals a deeper problem within contemporary environmental discourse: a tendency toward selective outrage, where culturally convenient targets are amplified, while politically complex or globally entrenched sources of environmental destruction-like war-are minimized or ignored.

Modern warfare is among the most resource-intensive and environmentally destructive human activities. Executive Vice President in SINTEF, Norway's largest research institute, Nils Rokke in an article at Forbes wrote, 'War is among the most destructive forces on Earth, and not just for the people caught in its path.While humanitarian impacts dominate headlines, the environmental costs are immense and largely ignored. Armed conflicts unleash unprecedented levels of greenhouse gas emissions and pollution from the fossil-fueled tanks, jets and warships to the vast industrial complexes that churn out ammunition, drones and military vehicles. This is not to be ridiculed as we are talking about a strong driver for conflicts, global warming and biodiversity attrition.'

Yet, it remains conspicuously under-represented in climate conversations. Recent conflicts have brought this contradiction into sharp focus. The war in Gaza, for instance, has generated tens of millions of tonnes of carbon emissions within months-comparable to the annual emissions of entire small nations.

Similarly, the ongoing conflict in Ukraine has produced emissions running into hundreds of millions of tonnes, driven by fuel-intensive military operations, infrastructure destruction and widespread fires.

The irony is stark. While a few hours of firecracker use during Diwali trigger nationwide campaigns and moral policing, the sustained environmental devastation caused by months or years of warfare rarely provokes comparable outrage. There are no global hashtags demanding 'eco-friendly warfare,' no celebrity campaigns urging restraint in missile usage and no widespread calls to hold militaries accountable for their carbon footprint. This disparity reveals a deeper issue within contemporary environmentalism-its susceptibility to selective outrage. Environmental concern, ideally, should be universal and impartial, guided by scientific evidence and ethical consistency. However, in practice, it often becomes entangled with cultural biases, political convenience and media narratives.

Festivals like Diwali are visible, predictable and culturally specific. They provide an easy target—one that can be criticised without geopolitical complications or economic repercussions. Questioning the environmental impact of a cultural practice is far less contentious than confronting the ecological consequences of global military powers or complex international conflicts. Moreover, there is a tendency to frame environmental responsibility in a way that disproportionately scrutinises traditional practices while overlooking industrial and institutional sources of pollution.

According to various studies, the contribution of firecrackers to annual air pollution levels is relatively small compared to emissions from vehicles, construction activities, coal-fired power plants and agricultural burning. Yet, the narrative often magnifies the former while downplaying the latter. This is not an argument to dismiss environmental concerns related to Diwali. Responsible celebration is important and there is merit in promoting eco-friendly alternatives. However, such advocacy must be grounded in proportion and fairness. Singling out one cultural practice while ignoring larger systemic issues undermines the credibility of environmental discourse. Equally important is the cultural dimension of the debate. Festivals like Diwali are not merely events; they are expressions of identity, community and continuity. When environmental arguments are framed in a way that appears to target specific cultural traditions, they risk being perceived as ideological rather than ecological. This perception, in turn, can create resistance and polarisation, making constructive dialogue more difficult.

In contrast, addressing the environmental impact of war requires confronting powerful interests and complex geopolitics. Military establishments are among the largest institutional consumers of fossil fuels, yet they operate with limited transparency in environmental reporting. International climate agreements often exclude military emissions, allowing a significant source of pollution to remain unaccounted for. Barry S. Levy, a researcher, physician and former president of the American Public Health Association notes in his paper 'The Impacts of War on Health, Human Rights and the Environment-An Overview' that nearly one-fourth of the world's population lives in regions directly affected by armed conflict. He emphasizes that in most wars, the majority of deaths occur among non-combatant civilians, who are often deliberately targeted as a strategy of war. Furthermore, large numbers of people are forcibly displaced, many within their own countries as internally displaced persons and others as refugees who cross international borders. As of the end of June 2024, it is estimated that approximately 123 million people were forcibly displaced worldwide, including 72 million internally displaced persons, 44 million refugees and 8 million asylum seekers. Beyond these humanitarian crises, war also exerts significant indirect impacts on the environment.

Another environment expert and Professor at University of Ioannina, Konstantinos T Kotsis in his paper The Impact of War on the Environment wrote, 'The conflict has historically inflicted profound and often long-lasting environmental damage, affecting ecosystems and communities in many ways. Throughout the 20th century and extending into the 21st century, wars have led to widespread deforestation, soil degradation and extensive air and water pollution, all of which directly affect human health and agricultural productivity in the short and long term. For instance, the ongoing conflict in Ukraine exemplifies how military operations can devastate natural resources, as noted in studies that meticulously document significant ecological impacts stemming from the violence of 2022. This tumultuous period saw not only increased atmospheric air pollution but also the systematic destruction of essential infrastructure, such as dams, irrigation systems and agricultural land, which escalated the ramifications of ecocide on local communities and wildlife populations.'

The scale of environmental destruction caused by war is not merely anecdotal; it is empirically documented and staggering in magnitude. A report by the UN Environment Programme (UNEP) has repeatedly warned that armed conflicts leave behind 'toxic legacies' that persist for decades, contaminating soil, water and air. During the Gulf War, for instance, the deliberate burning of over 600 Kuwaiti oil wells released an estimated 500 million barrels of oil into the environment, causing massive air pollution and long-term ecological damage. Similarly, the ongoing Russia-Ukraine War has been linked to widespread environmental degradation; according to assessments supported by UNEP and the World Bank, thousands of incidents of environmental harm have been recorded, including contamination of water bodies, destruction of forests, and damage to protected ecosystems. Carbon emissions from warfare further intensify the climate crisis. A study by the Conflict and Environment Observatory estimates that the first year of the Ukraine war alone generated approximately 120 million tonnes of carbon dioxide equivalent emissions-comparable to the annual emissions of a mid-sized industrialised country. A report by The Guardian, published on 9 January 2024 and authored by climate justice reporter Nina Lakhani, noted that 'The vast majority (over 99%) of the 281,000 metric tonnes of carbon dioxide (CO_2 equivalent) estimated to have been generated in the first 60 days following the 7 October Hamas attack can be attributed to Israel's aerial bombardment and ground invasion of Gaza, according to a first-of-its-kind analysis by researchers in the UK and US.'

If environmentalism is to be meaningful and effective, it must expand its scope to include these overlooked dimensions. The carbon footprint of war, the ecological damage of armed conflicts and the environmental cost of defence industries must become central to global climate discussions. Ignoring these factors not only skews our understanding of environmental challenges but also limits our ability to address them comprehensively. The current global context makes this imperative even more urgent. As conflicts continue to erupt and escalate, their environmental consequences accumulate silently. Forests burn, water sources are polluted, biodiversity is lost and greenhouse gases are released-all contributing to the broader crisis of climate change. These impacts do not respect national borders; they affect the global ecosystem as a whole.

At the same time, the focus on individual behaviour-what people eat, how they celebrate, what they consume-while important, should not overshadow the need for systemic change. Holding individuals accountable for small-scale practices while ignoring large-scale industrial and military activities creates a distorted narrative of responsibility. The selective outrage surrounding Diwali versus war is, therefore, not just a matter of inconsistency;

it is indicative of a deeper imbalance in how environmental issues are framed and addressed. It reflects a tendency to prioritise visibility over impact, simplicity over complexity and cultural critique over structural analysis. Breaking this narrative requires a shift in perspective. Environmentalism must move beyond symbolic gestures and embrace a more holistic approach-one that considers all sources of ecological harm, regardless of their cultural or political context. It must be guided by evidence, fairness and a commitment to addressing the most significant drivers of environmental degradation.

Bharat, with its civilisational ethos of harmony with nature, has much to contribute to this discourse. The principles embedded in its traditions, respect for all forms of life, balance between consumption and conservation and the recognition of nature's intrinsic value-offer a framework that is both ancient and relevant. Rather than viewing cultural practices as obstacles, they can be reinterpreted and adapted in ways that align with contemporary environmental needs. Eco-friendly celebrations, sustainable rituals and community-driven conservation efforts can bridge the gap between tradition and modernity.

At the same time, there must be a willingness to confront uncomfortable truths about global systems. The environmental cost of war cannot remain a peripheral issue. It must be brought to the forefront of climate discussions, policy frameworks and public awareness. In conclusion, the debate is not about choosing between culture and environment; it is about ensuring that environmental concern is applied consistently and fairly. Diwali's lights may briefly illuminate the night sky, but the fires of war cast a far longer and darker shadow over the planet. If we are truly committed to protecting the environment, our outrage must be guided not by convenience or bias, but by the scale and severity of the impact. Only then can environmentalism fulfil its true purpose-not as a tool of selective criticism, but as a universal commitment to safeguarding the Earth for all. ■

I झारखंड I

अभाविप ने सरकार पर लगाया भाषाई तुष्टिकरण का आरोप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने जेटेट परीक्षा की नई नियमावली में भोजपुरी और मगही भाषा को हटाए जाने को राज्य के साथ विश्वासघात बताया है। अभाविप के झारखंड प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी ने कहा कि यह निर्णय भाषाई विभाजन की आग भड़काने का खतरनाक षड्यंत्र है, जो राज्य को आंतरिक कलह और सामाजिक फूट की चपेट में झोंक देगा। उन्होंने सरकार पर भाषाई तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पलामू प्रमंडल सहित उत्तरी झारखंड के निवासी भोजपुरी-मगही को अपनी मातृभाषा मानते हैं। इन भाषाओं का उपयोग दैनिक जीवन, संस्कृति और शिक्षा में गहराई से जुड़ा है। फिर भी सरकार इस निर्णय से स्पष्ट संदेश दे रही है कि पलामू के लोग राज्य के अभिन्न अंग नहीं हैं। इससे भोजपुरी-मगही बोलने वाले विद्यार्थी जेटेट परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। राज्य सरकार क्षेत्र विशेष के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जो संविधान की भावना का उल्लंघन है। जबकि, झारखंड राज्य गठन के समय ही भाषाई विविधता को मजबूती देने का वादा किया गया था, लेकिन आज वही सरकार एक भाषा थोप रही है। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर युवाओं में विभाजन की साजिश निंदनीय है। क्षेत्र, भाषा, जाति या लिंग के नाम पर कोई भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा और भाषाई समानता और सम्मान के लिए लड़ेंगे। अभाविप ने जेटेट की नई नियमावली में भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल करने व राज्यस्तर पर भाषाई नीति में सभी स्थानीय भाषाओं को मान्यता देने की मांग की है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

Pakistan-Afghanistan conflict : An Overview

■ K. N. Pandita

In the month of Ramadhan, considered a holy month by the Muslims in which they are enjoined to perform acts of charity and benevolence, especially to their co-religionists, the Pakistan Air Force bombarded a hospital in Kabul where 400 patients undergoing treatment for drug addiction were killed. Pakistan said it was seeking revenge for the Afghan Taliban's attack on some Pakistani military posts along the Durand Line. The Islamic Republic of Pakistan scheduled the revenge from the Islamic Emirate of Afghanistan in the holy month of Ramadhan.

No Islamic country outright condemned the atrocious bombardment of a hospital and the taking of the lives of innocent civilians. The OIC, comprising 57 Islamic nations committed to protecting the life and interests of Muslims all over the world, did not bat an eyelid, not to speak of passing a resolution against a barbaric act vandalising co-religionists. This shows that OIC is nothing but a bundle of hypocrisy.

On the other hand, if a hardcore terrorist gets killed in an encounter with the externally sponsored terrorists, the OIC forthwith scrambles for an emergency meeting and all the 57 members of the organisation rush to sign a resolution against India. It is a different thing that after signing the resolution, most of the signatories sneak into the nearby Indian embassy to assure the Indian diplomatic staff that the resolutions are a humbug and they want to continue normal and routine trade relations with India.

Armed clashes between the Taliban and the Pakistani army on the border have almost become a routine matter. There is hardly a week that goes by that casualties on either side do not take place. The OIC members are comfortable with the death toll of Muslim fighters on either side rising with each passing day.

ROOT CAUSE OF ANIMOSITY

The root cause of animosity between the two countries is primarily the Durand Line, which is a colonial legacy of British India. The Durand Line agreement was signed on 12 November 1893 in Kabul, Afghanistan. It was negotiated by Sir Henry Mortimer Durand, the Foreign Secretary of British India and Amir Abdur Rahman Khan, the ruler of Afghanistan, to define their respective spheres of influence.

The British sought a secure, established border to prevent Russian expansion towards India during the 'Great Game'. The line created a 2,640 km (roughly 1,640 miles) border, cutting through Pashtun and Baloch tribal territories.

THE DISPUTE

While considered an international border by Pakistan as the successor to British India, Afghanistan never recognised the dividing line. According to Kabul, the sovereignty of the British lapsed with the partition of India in 1947. Apart from that, Kabul has been asserting that the consent of millions of Pashtuns, whose land was divided, was never sought. As such, the Durand Line had no legitimacy whatsoever.

The Kabul government further asserted that the Pashtun and the Baluch people had the right to the option of independence, but that right was never conceded. Not only that, the Kabul government never

recognised Pakistan as an independent state and opposed its membership in the United Nations, arguing that if Kabul recognised Pakistan, it would mean recognition of the Durand Line as well, which was fundamentally against Afghanistan's stand on the issue.

But Pakistan claimed that it inherited the legacy from the British rule over India when India was partitioned in 1947. Pakistan has been treating the Durand Line as the international border between Afghanistan and Pakistan. Since the Durand Line is the legacy of British colonial power, the Anglo-American bloc and the Western powers have been generally buying the Pakistani story and seldom pay heed to the cogent arguments of Afghanistan.

US-PAK COMBINE

The Durand Line controversy subsided temporarily during the Soviet incursion into Afghanistan and the involvement of America and Pakistan in that strife. The US whipped up communal passions among the Afghan Mujahedin, something which the Afghans had not been happy with. Gen Zia of Pakistan became the conduit for the transfer of American arms and funds to the Afghan mujahedin.

In 1996, the Taliban captured Kabul and established the first regime after deposing and hanging Dr. Najibullah, the President of Afghanistan. Once the Taliban seized power in Kabul, they declared Afghanistan an Islamic state and promulgated the Islamic Sharia, discarding the constitution. The first Taliban regime brutally treated the Afghan women. Afghan girls were disallowed to go to schools, the veil was strictly enforced, women were not allowed to come out of their homes all by themselves and the services of many female workers in many institutions were terminated.

Resistance forces lost popularity because of their atrocious treatment of Afghan women and forced implementation of extremist conservatism. Finally, with the support of Pakistan and a covert green signal from the CIA, the Taliban group surfaced in Kandahar and confronted the haywire resistance forces. In 2001, the US landed its troops in Afghanistan with the intention of subjugating the Taliban. The US-Afghan war continued for nearly two decades, during which time both sides incurred considerable loss of men and material.

PAK SEEKS STRATEGIC DEPTH

Pakistan has always shown its political interest in Afghanistan. Finding that there prevailed political uncertainty in that country, Pakistan posed as their well-wisher and covertly lent the Taliban some support. But at the same time, Islamabad tried to convince Washington that it was an outright supporter of the US. By playing the double role, Pakistan succeeded in garnering huge funds from the US and, at the same time, playing tricks with the Taliban.

The intention of Pakistan has always been to find strategic depth westward. After its crushing defeat at the hands of India in the Bangladesh war, Pakistan has been nursing the fear that India can launch an attack and cripple the Pakistani state. It finds itself sandwiched between Afghanistan and India. Therefore, she has been in search of strategic depth westward. A weak and backward Afghanistan suits them.

KABUL FALLS TO THE TALIBAN

However, when the Taliban gained control over Kabul and the US forces ran away from Afghanistan, leaving behind all the billions of dollars worth of military equipment, including helicopters, tanks and vehicles. Pakistan thought now was the time for her to pose as the boss of Afghanistan. This was only a fantasia and the ISI soon realised that the Taliban were in no mood to play the second fiddle. They had fought the world's most powerful country and had made tremendous

sacrifices. They told Pakistan, thanks for your support, true or fake, but you'd better confine to your country's problems and not interfere in Afghanistan's internal affairs.

TTP

Along with this, the Taliban once again raised the Durand Line issue and said categorically that they do not recognise it. While differences were simmering between them, another situation developed in the region. Owing to Pakistan's pro-Punjabi policy and also blatant discrimination of the Pushtun population in the Pakhtunkhwa region, the warlike Pushtuns raised the banner of rebellion and with the passage of time, became a very formidable anti-army force. They demanded autonomy from Pakistan and openly aligned with the Taliban, saying that they were brethren and could not be separated by an illegal Durand Line. They took up arms and are now known as Tehreek-i-Taliban Pakistan or TTP. The Pakistan army has been fighting the TTP and suffering immense losses. True, more often than not, the TTP fighters, after conducting gorilla operations in Pakhtunkhwa/Waziristan, seek safe haven across the line in Afghan villages and towns. Pakistan accuses the Taliban of providing a safe haven to the TTP. Kabul denies the accusation but at the same time calls TTP their blood brothers.

INDO-AFGHAN RELATIONS

Cordial relations between India and Afghanistan have a long history. Afghanistan gave shelter to the Indian nationalists fighting against colonial rule. The post-independence government of India has invested billions of dollars in providing necessary infrastructure to Afghanistan, like roads, schools, hospitals, bridges, dams, medical facilities and scholarships to Afghan students. Afghans are fully conscious that India has been a selfless supporter of their welfare and prosperity. The Parliament House and many more essential structures have been built by India. All this helped in cementing the friendship between the two countries. The recent seven-day visit of Afghan leader Mulla Muttaqi to India was a very important event during which many bilateral agreements were signed.

However, it remains to be said that India shall have to share its responsibility of lending practical and feasible support to Afghanistan at a time when it is facing air strikes from Pakistan and does not have its air force to retaliate. India should take note of this and work out a scheme that ensures the safety of Afghans against wanton attacks of a desperate enemy. Under the provisions of international law, India is obliged to take protective measures that ensure the safety of a friendly country under attack. ■

सुधी पाठकों !

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' अप्रैल-2026 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों एवं खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'

26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नई दिल्ली-110002

फोन : 011-23216298

www.chhatrashakti.in

rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com

www.facebook.com/Rchhatrashakti

www.twitter.com/Rchhatrashakti

www.instagram.com/ Rchhatrashakti

गुरु दक्षिणा

■ डा. रजत शर्मा

दूरदर्शी राष्ट्रनायक डा. केशव बलिराम हेडगेवार की बीजदृष्टि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' की वह उर्वर भूमि है, जो उसे विशिष्ट बनाती है। साथ ही संघ को विशिष्ट बनाती हुई उसकी एक विशेषता उसका 'आर्थिक स्वावलंबन' है। वास्तव में यह वह चिर-नूतन पद्धति है, जो संघ को आर्थिक अवलंबन से सुरक्षित करते हुए स्वयंसेवक में राष्ट्र-समर्पण का भाव जागृत करती है। संघ में इसे 'गुरु दक्षिणा' के नाम से जाना जाता है। दरअसल, संघ की कार्य पद्धति उसके अस्तित्व में आने से पहले पूर्व नियोजित नहीं हुई। अपितु यह पद्धति समयांतराल में विकसित तथा हिंदू जीवन पद्धति के अनुकरण पर आधारित है। समय की आवश्यकता के साथ इस पद्धति का विकास हुआ है।

भारत में जब स्वतंत्रता ही प्रत्येक व्यक्ति का विचार था, उस समय अनेक संगठनों की रचना स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से अस्तित्व में आई। यह संगठन सात्विक दृष्टि से बनते अवश्य थे, लेकिन कभी आर्थिक तो कभी अन्य कारणों से समाप्त हो जाते थे। इसीलिए डा. केशव हेडगेवार ने यह विचार किया कि आर्थिक स्वावलंबन के बिना संगठन की निरंतरता बने रहना संभव नहीं है। साथ ही आर्थिक स्वावलंबन के बिना संगठन के मूल चरित्र का बना रहना भी संभव नहीं है। इसीलिए प्राचीन काल से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक संरचना को संगठन की आर्थिक संरचना के रूप में आत्मसात किया।

आरंभ में संघ कार्य करते हुए यह विचार भी आया कि दान-दाताओं के मन में एक भाव संघ के प्रति जागृत होता था कि आवश्यकता पड़ने पर संघ के स्वयंसेवक उनकी सहायता करेंगे। शादी विवाह में संघ के घोष का उपयोग किया जा सकेगा। अतः इस प्रकार 'हिंदुओं के संगठन' के सात्विक लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं था। वहीं, दान में देने वाले में 'देने का अहम्' और लेने वाले में 'आत्मग्लानि' का भाव सहज ही पैदा हो जाता है। ऐसे में स्वयंसेवकों के मनोभाव का शुद्ध रहना भी संभव नहीं था। इस कारण समाज संगठन के लक्ष्य में समाज के दो सदस्यों का आपस में संबंध स्थापित होना संभव नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों के चिंतन का परिणाम है - संघ की 'गुरु दक्षिणा'।

संघ में 'गुरु दक्षिणा' हिंदू जीवन दृष्टि का विकास है। मंदिरों में धर्म एवं सामाजिक सेवा के नाम पर श्रद्धा भाव से दक्षिणा देने की परंपरा भारत में प्राचीन काल से रही है। इसके साथ ही भारत की ग्राम स्वराज्य की साकार स्थिति भी सामूहिक समाज की जिम्मेदारियों पर मजबूत थी। धर्मपाल जी के लेखन और ब्रिटिश दस्तावेजों में इसके प्रमाण हैं। इसी प्रकार 'गुरु दक्षिणा' देते हुए दाता में ना तो उपकार का भाव होता है, और ना ही दिए हुए स्थान पर अधिकार का अहं होता है, अपितु वह श्रद्धा से सामाजिक उद्धार के लिए दक्षिणा देता आया है। परंपरा से धन को ज्ञान का मूल्य निर्धारक नहीं माना गया है। गुरु दक्षिणा धन से ऊपर उठकर समर्पण को महत्व देती है। संघ में इसी पारंपरिक भाव-भूमि को प्रत्येक स्वयंसेवक में जागृत करने के लिए इस पद्धति का विकास किया गया।

इसी दृष्टि के साथ सर्वप्रथम 3 जुलाई 1928 को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन संघ में गुरु पूजन प्रारम्भ हुआ। भगवा ध्वज को गुरु के रूप में रखा गया और गुरु दक्षिणा की पहली भेंट 84 रुपए और कुछ आने एकत्रित हुए। यह संघ के एक महत्वपूर्ण पक्ष व्यक्ति निष्ठा के स्थान पर ध्येय निष्ठा को प्रकट करता है। गुणों के प्रतीक को गुरु रूप में सामने रखकर नित्य साधना करना तथा वर्ष में एक बार धन समर्पण के लिए एकत्र होना यह संघ की अनूठी विशेषता है। 'गुरु दक्षिणा' में स्वयंसेवक सामर्थ्य के अनुसार संपत्ति का कुछ भाग गुरु (भगवा ध्वज) के प्रति समर्पित करता है। संघ में एक बालक भी अपने रोजखर्च से एक-एक रुपए बचाकर अपनी संपत्ति का भाग अर्पित करता है तो धनाढ्य स्वयंसेवक भी सामर्थ्य के अनुसार राशि का समर्पण करता है। संघ की गुरु दक्षिण में राशि की महत्ता उतनी अधिक नहीं है, जितनी समर्पण भाव की। यह समर्पण स्वयंसेवक में संगठन के प्रति अपनत्व की दृष्टि पैदा करता है। स्वयंसेवक को आभास होता है कि यह उसका अपना संगठन है और उसके संचालन की जिम्मेदारी उसकी अपनी है। यही गुरु दक्षिणा का एक सुंदर पक्ष है, जो समयांतराल में भी संघ को और अधिक संगठित तथा और अधिक प्रासंगिक बने रहने की क्षमता प्रदान करता है। ■

(लेखक दिल्ली स्थित लक्ष्मीबाई कालेज में सहायक प्राध्यापक हैं।)

सामाजिक-सांस्कृतिक एकता का दर्शन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), एवं विद्यार्थी सेवा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा आयोजित स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन रीजनल अंडरस्टैंडिंग (सेरू) यात्रा गत 11 मार्च को लद्दाख वापसी के साथ संपन्न हुई। सेरू यात्रा में लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों- नुब्रा, कारगिल, लेह, लामायुरु, शांग, न्योमा और जंस्कार निवासी छात्र-छात्राएं शामिल रहे। गत 26 फरवरी से प्रारम्भ हुई यात्रा में इस बार 30 छात्र-छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल ने देश की राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम (हरियाणा), चंडीगढ़, कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), जम्मू और श्रीनगर का भ्रमण किया।

राष्ट्रीय एकता यात्रा सेरू का एक विशेष आयाम यह है कि प्रतिनिधियों को प्रत्येक राज्य में स्थानीय कार्यकर्ताओं के परिवारों के साथ ठहराया जाता है, जिससे उन्हें 'घर से दूर, घर जैसा' वातावरण प्राप्त होता है। अबकी बार यात्रा के दौरान लगभग 75 से अधिक परिवारों में प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें स्थानीय संस्कृति, खान-पान और जीवनशैली को निकट से समझने का अवसर मिला।

अभाविप के प्रकल्प 'सेरू' द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के अंतर्गत लद्दाख से यह सभी प्रतिनिधि सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत के बाद प्रतिनिधियों ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण किया, जहां विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें दिल्ली विधानसभा के इतिहास से परिचित कराया। इसके उपरांत अभाविप नीत दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया गया। बाद में प्रतिनिधियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय की उस ऐतिहासिक कोठरी का भ्रमण किया, जहां स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी भगत सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। बाद में प्रतिनिधिमंडल के

सदस्यों ने मेजबान परिवारों से परस्पर संवाद किया और फिर उनके निवास पर रात्रि विश्राम किया।

27 फरवरी को छात्र प्रतिनिधियों ने संसद भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय के भ्रमण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के लोकतांत्रिक मूल्यों को समझा। केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह के आवास पर हुए एक संवाद सत्र में भविष्य से संबंधित विषयों पर एक सार्थक चर्चा हुई। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के बाद अगले दिन सभी प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति भवन का भ्रमण किया और वहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित हुए। छात्र प्रतिनिधियों का दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद के साथ भी का संवाद हुआ।

दिल्ली के बाद हरियाणा स्थित गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर लद्दाख और हरियाणा की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का मंचन हुआ तथा विश्वविद्यालय के कुलपति से भी संवाद हुआ। बाद में चंडीगढ़ में विद्यार्थियों ने होली उत्सव में भाग लेकर सांस्कृतिक समरसता का अनुभव किया तथा पंजाब विश्वविद्यालय एवं चंडीगढ़ का भ्रमण भी किया।

छात्र प्रतिनिधियों ने हिमाचल प्रदेश प्रवास के

दौरान बौद्ध गोम्पा एवं धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के साथ ही रोहतांग टनल और सिस्सू जैसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया। जम्मू एवं कश्मीर में उपराज्यपाल से मुलाकात करने साथ ही प्रतिनिधियों ने भारत-पाकिस्तान सीमा और सैन्य परेड भी देखी। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लद्दाख के नौजवानों को देश और समाज के लिए योगदान देने की प्रेरणा दी और उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और अनुभवों से सीखने तथा समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

जानकारी हो कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत अभाविप द्वारा आयोजित सेरू यात्रा का उद्देश्य लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को देश के विभिन्न भागों में भेजकर वहां की संस्कृति, रहन-सहन, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक जीवन से परिचित कराना है। साथ ही, कार्यक्रम के माध्यम से लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देशभर में पहुंचाना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। यात्रा का आरम्भ 1992 में हुआ था। लद्दाख देश के सबसे सुदूर स्थानों पर स्थित है। यहां के नागरिक विषम परिस्थिति में रहते हैं तथा यह चीन और पाकिस्तान दोनों देशों से सटा हुआ क्षेत्र है। 1992 में सामरिक तथा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील लद्दाख में 20 छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल गया था। उस प्रतिनिधिमंडल में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू के छात्र शामिल थे। लेकिन 1990 के दशक में जम्मू एवं कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद के कारण यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। 2025 में इस महत्वपूर्ण पहल को पुनः प्रारंभ किया गया। 2026 में हुई दूसरी यात्रा में लद्दाख से आए छात्र प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न राज्यों की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझने का अवसर मिला। वास्तव में देखा जाए तो यह यात्रा केवल एक शैक्षणिक भ्रमण नहीं, अपितु विद्यार्थियों के बीच आपसी संवाद, सहयोग और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का एक सशक्त माध्यम है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

| प्रतिक्रिया |

जनजातीय गौरव की विरोधी है ममता सरकार : अभाविप

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान संथाल समाज द्वारा आयोजित '9 वें अंतरराष्ट्रीय संथाल कांफ्रेंस' में व्यवस्थागत प्रशासनिक खामियों और राष्ट्रपति की गरिमा अनुसार स्थान न उपलब्ध कराने की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। अभाविप का कहना है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की प्रथम नागरिक के कार्यक्रम में ऐसा कुप्रबंधन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय अंतरात्मा पर चोट है। राष्ट्रपति के आगमन पर प्रोटोकॉल का पालन न करना राज्य की ममता सरकार के नाकारेपन और उदासीनता का परिचायक है, जिससे राज्य सरकार की जनजातीय वर्ग तथा महिला विरोधी छवि स्पष्ट होती है।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने गत 7 मार्च को अपने एक बयान में कहा कि यह घटना भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक दाग की तरह अंकित रहेगी। जनजातीय वर्ग से आने वाली राष्ट्रपति को संथाल अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस के आयोजन के लिए यथाउचित स्थान नहीं उपलब्ध कराया गया, जिससे चार बार कार्यक्रम स्थल बदलना पड़ा। यह घटना इसलिए भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति को अपने ही देश में कार्यक्रम के लिए ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ममता सरकार की प्रशासनिक अराजकता किसी से छिपी नहीं है और उनका जनजातीय समाज व महिला विरोधी चरित्र बार-बार सामने आ रहा है। अभाविप ममता सरकार के इस कुकृत्य की घोर निंदा करती है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

व्यक्ति एक-आयाम अनेक

■ डा. प्रवेश कुमार

संविधान के रचनाकार बाबा साहब भीम राव रामजी आंबेडकर ने मात्र वंचितों, दलितों के कल्याण की ही बात नहीं की, बल्कि उनके चिंतन के केंद्र में भारत और भारतीय समाज ही सदैव रहा। इसीलिए वह कहते हैं कि पहले और अंतिम रूप में वह एक भारतीय हैं। डा. आंबेडकर ने आजीवन भारत के उस भाव के लिए काम किया, जिसका मूल तत्व 'सर्वे भवंतु सुखिनः' है। जैसे-जैसे डा. आंबेडकर पर काम हो रहा, वैसे-वैसे उनके जीवन के कई आयाम निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता हैं, क्या वास्तव में वो सिर्फ दलित समाज के ही नेता थे? इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

भारत के इस महान सपूत का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू (मध्य प्रदेश) में हुआ था। इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना मे सूबेदार के पद पर कार्यरत थे, वही माता भीमाबाई एक गृहिणी थी। अपने एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक महादेव आंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, के कहने पर डा. आंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर आंबेडकर जोड़ लिया जो उनके गांव के नाम 'अंबावडे' पर भी आधारित था। उनका जन्म हिंदू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था क्रम में निम्न समझे जाने वाली महार जाति में हुआ, जिसके कारण उनको सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। समाज में व्याप्त सामाजिक कुरूतियों ने डा. आंबेडकर के मन पर गहरा प्रभाव डाला। तमाम बाधाओं को सहते हुए भी डा. आंबेडकर ने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया। डा. आंबेडकर अपने एक अन्य शिक्षक केलुसकर के भी अधिक प्रिय थे। इसी शिक्षक की सिफारिश पर बड़ौदा रियासत से आंबेडकर को विदेश में जा कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृति मिली। डा. आंबेडकर ने भारत आकर बड़ौदा रियासत की छात्रवृति में निहित अनुबंध के अनुसार बड़ौदा रियासत में रक्षा सचिव के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। लेकिन बड़ौदा में उनके सामने रहने-खाने की अधिक समस्या आ खड़ी हुई क्योंकि बड़ौदा में भी समाज का ताना-बाना उसी प्रकार का था, जिसे उन्होंने अपने बाल्यकाल में झेला था। बड़ौदा में उनको रहने के लिए कोई घर नहीं मिला। कार्यालय में उनके द्वारा छुई किसी फाइल को छूने में सहकर्मियों को असहजता होती थी। उन्होंने इसकी जानकारी रियासत के राजा को दी, लेकिन जब कहीं से कोई सहायता नहीं मिली तो उन्होंने रक्षा सचिव पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद वह मुंबई आ गए। यहां आकर वह सिडनहॅम कालेज में पढ़ाने लगे, पर यहां भी उन्हें सहयोगी शिक्षकों का भेदभाव झेलना पड़ा और फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके

बाद डा. आंबेडकर वकालत के पेशे में आए, लेकिन यहां भी उनको सफलता नहीं मिली। लगातार मिलती असफलताओं के बाद भी डा. आंबेडकर के मन में किसी समाज के प्रति दुर्व्यवहार का भाव नहीं आया क्योंकि भारत का मूल तत्व डा. आंबेडकर के मानस में भीतर तक घर कर चुका था।

यही कारण है कि जब बाबा साहब ने समान मताधिकार का मुद्दा साउथबरो कमेटी (1918-1919), जिसे 'मताधिकार समिति' के रूप में भी जाना जाता था, के सामने रखा, तब उन्होंने बिना किसी भेद के 'एक मत, एक मूल्य, एक व्यक्ति' के विचार पर आधारित मताधिकार की मांग की। उन्होंने उद्यमिता और छोटे काम-धंधों की बात की, जिसमें महिलाओं और वंचितों को छोटे उद्यमी बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि छोटे एवं मझोले उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सरकार लोगों को विशेषकर महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराए। डा. आंबेडकर ने यहां किसी एक जाति-वर्ग की बात नहीं की, बल्कि सम्पूर्ण समाज की बात कही।

भारत में अपना केंद्रीय बैंक होना चाहिए-इस विचार को हिल्टन यंग आयोग (1925) और रॉयल कमीशन के सामने रखने वाले डा. आंबेडकर ही थे। इसी आधार पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना हुई। भारत का आर्थिक ढांचा कैसा हो? किन उद्योगों के साथ कृषि भी आगे बढ़े? इसकी चिंता उनके आर्थिक चिंतन में देखी जा सकती है। डा. आंबेडकर कहते है कि देश के लिए भारी उद्योगों की नितांत आवश्यकता है, लेकिन खेती-किसानी से भारत का बड़ा वर्ग संलग्न है, इसलिए उसको भी उन्नत तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता है। डा. आंबेडकर ने कृषि भूमि का छोटा होने को किसानों की दयनीय परिस्थिति के लिए एक कारण माना और इसीलिए सामूहिक खेती करने का विचार दिया, जिसमें लागत कम, लाभ अधिक तथा जोखिम कम होता है।

डा. आंबेडकर ने भारतीय मुद्रा (रुपए) की समस्या, महंगाई तथा विनिमय दर, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रशासन एवं वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध ही नहीं किया, बल्कि इन मुद्दों से सम्बंधित समस्याओं के तार्किक एवं व्यावहारिक समाधान भी दिए।

1923 में डा. आंबेडकर ने वित्त आयोग के मुद्दे को उठाया और यह मांग की कि प्रत्येक पांच वर्ष में वित्त आयोग की रिपोर्ट आनी चाहिए। एक श्रमिक नेता के रूप में डा. आंबेडकर ने 1926 में मजदूर संगठनों की वकालत की, मज़दूरों के काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए, मजदूरों में भी महिलाओं और पुरुषों में काम के घंटे भिन्न होने चाहिए जैसी मांग डा. आंबेडकर द्वारा उठायी गई। जब वह वायसराय की काउन्सिल में श्रम मंत्री (1942) बने तो सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार कार्यालय की स्थापना, कर्मचारियों का राज्यकृत जीवन बीमा आदि सारे विषयों पर नीति-निर्माण कराने में डा. आंबेडकर की महती भूमिका रही।

महिलाओं के उद्धारक के रूप में 1928 में डा. आंबेडकर ने महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ की मांग की। 1929 में बॉम्बे विधानसभा में बिल रखा जो बाद में पारित हुआ, वही स्वतंत्र भारत में हिंदू कोड बिल लाने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। भविष्य की योजनाकर्ता की भूमिका के रूप में देश में बांध परियोजना विकास के लिए उन्होंने दामोदर बांध परियोजना बनाई, जो देश के विकास का वाहक बन गई।

यह उनकी दूरदर्शिता थी। डा. आंबेडकर ने भारत के निर्माण के लिए अपना एक-एक पल दे दिया लेकिन फिर भी उनके योगदान के लिए उन्हें उनके परिनिर्वाण के लगभग 34 वर्षों के बाद भारतरत्न मिला। वर्तमान सरकार ने डा. आंबेडकर के व्यक्तित्व से जुड़े कई आयामों को उभारने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि जिन डा. आंबेडकर को देश एवं दुनिया में कमजोर, वंचित वर्गों की एक मजबूत आवाज़ के रूप में ही जाना जाता था, वहीं आज डा. आंबेडकर अध्ययन केंद्रों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के कई और आयाम उभर कर दुनिया के सामने आएं हैं। ■

National Legal Conclave Highlights Vision of 'Viksit Bharat-2047'

■ Soorya Gayathri T.V.

A two-day national-level legal conference organised by the Forum of Tamil Nadu Law Students (FOTLAWS), concluded at VIT Chennai on March 22, bringing together around 750 law students, academicians and legal experts from across Tamil Nadu and Puducherry. The conference focused on the evolving dimensions of legal education and its role in achieving the vision of 'Viksit Bharat 2047'.

The conference was centred on contemporary legal developments, including Artificial Intelligence, Cyber Law and Intellectual Property Rights, while also encouraging discourse on constitutional values and governance. It provided a platform for academic exchange through paper presentations and direct interaction between students and distinguished members of the bar, bench, and legislature.

The conference was inaugurated by Union Minister of Parliamentary Affairs and Minority Affairs Kiren Rijiju, along with Justice R. Suresh Kumar of the Madras High Court. The inaugural session began with the national song and Tamil Thai Valthu.

In his inaugural address, Union Minister Rijiju underlined the importance of a robust and indigenous legal framework that

evolves with contemporary challenges while remaining rooted in India's civilizational values. He also highlighted Tamil Nadu's strong academic and cultural traditions.

Justice R. Suresh Kumar, in his keynote address, emphasized the dynamic nature of jurisprudence and urged students to approach legal education with discipline, ethical grounding and social responsibility.

Dr. G. V. Selvam, Vice President of VIT, delivered the welcome address, highlighting the importance of legal consciousness among students in a rapidly transforming society. Shravan B. Raj, ABVP National Secretary, in his felicitation address, outlined the objectives of FOTLAWS and emphasized its contribution to student engagement and legal awareness. Dr. G. Viswanathan, Founder and Chancellor of VIT, in his presidential address, stressed the need to improve India's Gross Enrolment Ratio in higher education to match global standards.

The conference featured six thematic sessions addressing various aspects of law and governance. The first session, chaired by Justice L. Victoria Gowri, focused on 'From Colonial Chains to Constitutional Sovereignty,' discussing India's constitutional evolution and the significance of fundamental rights and the Basic Structure Doctrine.

The second session included paper presentations across seven themes such as Constitutional Rights, Cyber Law, Artificial Intelligence, Environmental Law and Family Law. Around 120 teams participated, with the top three teams recognised during the valedictory ceremony.

The third session, led by Justice S. Srimathy, examined the role of women in the legal profession under the theme 'Women Jurists for a Developed Bharat.' The discussion highlighted gender equality, constitutional values, and the need to address systemic challenges faced by women in law.

The fourth session, addressed by Additional Solicitor General A.R.L. Sundaresan, focused on 'Ethics, AI & The Future of Litigation,' emphasizing the importance of integrity in legal practice and the balanced use of artificial intelligence.

The fifth session, chaired by Justice D. Bharatha Chakravarthy, explored the 'Use of AI in Legal Landscape,' discussing the role of technology as an assistive tool while reaffirming the importance of human judgment in legal reasoning.

The sixth session, chaired by Justice G. R. Swaminathan, focused on 'Integrating Indian Knowledge Systems in Jurisprudence,' highlighting the relevance of traditional knowledge systems and values in modern legal thought.

The conference concluded with a valedictory session graced by the Governor of Tamil Nadu, Rajendra Vishwanath Arlekar and Justice Kumaresh Babu. The dignitaries emphasized the importance of empathy, ethics and character in the legal profession.The session included a conference report presentation, presidential remarks and addresses focusing on justice delivery, constitutional responsibility and the role of legal professionals in society.

Governor Arlekar, in his address, urged students to prioritize humanity and compassion in the practice of law, stating that justice must always remain people-centric. Justice Kumaresh Babu, in his keynote address, spoke on the Constitution as an instrument of social transformation. Dr. Y. Nagalingam, National Vice-President of ABVP, also addressed the gathering, encouraging students to explore India's classical texts like the Thirukkural for ethical and legal insights.

The conference provided a platform for students to engage with contemporary legal issues and interact with members of the judiciary, legal professionals and academicians. NEEDHIKKALAM 2026 highlighted the role of legal education in shaping responsible professionals and contributing to national development. ■

राष्ट्रभक्ति की अमर पुकार

■ चेतस सुखाड़िया

वन्देमातरम् भारत के इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय की गाथा है, जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम की आत्मा को स्वर दिया, जिसने भारत माता के चरणों में भावों का सागर उड़ेल दिया और जिसने प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्वंत्रता के लिए धधकती उस ज्वाला को मशाल बना दिया-वह अध्याय है 'वन्देमातरम् की कहानी।

'वन्देमातरम्' के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह एक ऐसा इतिहास है जिसने न केवल स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, बल्कि राष्ट्रीय मनोभाव की पहचान भी बनाई। जिस प्रकार स्वतन्त्रता के काल में वन्देमातरम् क्रांतिकारियों के लिए देश पर बलिदान होने का एक महामंत्र था, उसी प्रकार वर्तमान समय में युवाओं के लिए भारत माता को समृद्ध एवं सशक्त बनाने का संकल्प है वन्देमातरम्। वन्देमातरम् में दो शब्द है, परंतु इन दो शब्दों में भारत की पूरी सभ्यता, संस्कृति, संघर्ष, स्वाभिमान, राष्ट्रभाव और बलिदान की गूंज समाई हुई है।

वन्देमातरम्... यह केवल उच्चरित शब्द नहीं है, यह भारतीय आत्मा का वह शाश्वत निनाद है, जो पिछली डेढ़ शताब्दी से अनवरत गुंजित हो रहा है। यह मात्र गीत नहीं, राष्ट्र-जागरण का वह दिव्य महामंत्र है, जिसने पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े भारत को आत्मबोध का प्रकाश दिया, जिसने निराशा के घोर तमस में अस्मिता की ज्योति प्रज्वलित की और संघर्ष को संबल एवं स्वाधीनता को स्वरूप प्रदान किया। 1870 के समय बंगाल भी ब्रिटिश शासन के अधीन था। वन्देमातरम् के रचयिता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय-केवल एक विद्वान या साहित्यकार नहीं थे, वह एक राष्ट्रयोगी थे। एक युवा साहित्यकार, जो रोजाना अंग्रेजों की सख्ती देखते थे। लोगों की आंखों में डर, दिलों में निराशा और भारत माता की गोद में थी असहायता। मन में पीड़ा थी-अपनी मातृभूमि पर पराधीनता की और हृदय में संकल्प था-भारत में नवजागरण का, नवजागरण के आरंभ का। ऐसी परिस्थितियों में बंकिमचंद्र ने सोचा कि क्या भारत को एक ऐसा गीत नहीं मिल सकता, जो लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर दे? देश अपने पहले स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की निष्फलता से पैदा हुई घोर निराशा से उभर रहा था। यहीं से कहानी शुरू हुई-एक क्रांति की, एक मातृ-भक्ति की, एक राष्ट्र-जागरण की।

एक दिन संध्याकाल में बंकिमचंद्र खेतों के रास्ते लौट रहे थे। हल्की हवा चल रही थी, धान की बालियां हिल रही थीं, कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी। ऐसे में उन्हें लगा-'क्या हमारी यह धरती सच में कम सुंदर है? क्या यह हमारी मां नहीं है? क्या इसे वंदन करने के लिए भी अनुमति चाहिए?' उस शाम उनकी आंख में आंसू थे और दिल में पहली बार धुन उठी-वन्देमातरम् सुजलाम, सुफलाम, मलयज, शीतलाम'(हे मां, तुम्हें

मेरा प्रणाम है। हे मां, तुम पानी से भरी हुई हो, फलों से भरी हुई हो। हे मां, तुम्हें मलय से आती हुई हवा शीतलता प्रदान करती है। हे मां, तुम फसल से ढकी रहती हो। हे मां, तुम्हें मेरा प्रणाम है।)

इसी भावना से 1875 में 'वन्देमातरम्' की रचना हुई। बंकिमचंद्र ने इस गीत को अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ (1882) में शामिल किया। यह उपन्यास मात्र साहित्य नहीं था-यह भारत के पुनर्जागरण का घोष था। जब 'वन्देमातरम्' आनंदमठ उपन्यास में प्रकट हुआ, तो यह केवल गीत नहीं रहा-यह भारत की अंतर आत्मा का उद्घोष था। उसी क्षण से यह शब्द एक गीत नहीं, आंदोलन बन गया। देश का हर कोना जैसे जाग उठा। जो इसे सुनता, वही बदल जाता। जो इसे गाता, वह निडर हो जाता। राष्ट्र भक्ति के रंग में रंग जाता। यह गीत भारत की नसों में नवजीवन भरने लगा। किसी ने किसी को कहने की जरूरत ही न समझी, हर दिल पर, हर सांस पर बस एक ही स्वर-वन्देमातरम् सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई और आज भी राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। गीत ने यह भी सिखाया कि राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि एक जीवंत, संवेदनशील, मातृस्वरूपा सत्ता है, जिसके प्रति हमारी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण हो। यह गीत भारतीय जीवन-दर्शन का प्रतीक है, जहां राष्ट्रभक्ति केवल राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि भक्ति, साधना और सेवा का रूप ले लेती है। वन्देमातरम् स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रथम राष्ट्रगीत बन गया। 20वीं सदी के आरंभ में जब देश में राजनीतिक चेतना तेज़ हुई, तो कांग्रेस के सत्रों में, जनसभाओं में, सत्याग्रहों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में-हर जगह गूंजने लगा-'वन्देमातरम्-वन्देमातरम्'।

1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने 'वन्देमातरम्' को धुन में पिरोया और कलकता कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया, जिससे इसे वाणी और अमरता प्राप्त हुई। यह गीत भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़कर पूरे देश में गूंज उठा। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने इसका तमिल अनुवाद किया और पंजाब में क्रांतिकारियों ने इसे गाते हुए ब्रिटिश राज को खुली चुनौती दी। जब अंग्रेजों ने अपनी कुटिल चाल चलते हुए बंगाल विभाजन की योजना बनाई तो 1905 में बंग-भंग आंदोलन का जन्म हुआ। बंग भंग आंदोलन के समय भी वन्देमातरम केवल एक गीत नहीं रहा। इसकी गूंज विद्यालयों में, सभाओं में, जुलूसों में और हर उस मार्ग पर सुनाई देती थी, जहां स्वतंत्रता का स्वप्न जीवित था। फांसी के तख्ते पर चढ़ते क्रांतिकारियों के होंठों पर अंतिम उच्चारण भी वन्देमातरम ही था। यह गीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया।

ब्रिटिश सरकार ने देखा कि यह दो शब्द, उनकी नींद उड़ाने लगे हैं। यह गीत जनता को एकजुट कर रहा है। न ही किसी ने हथियार उठाए, न ही किसी ने युद्ध छेड़ा-पर लोग एकजुट हो रहे थे क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि किसी भी क्रांति का आरंभ तलवार से नहीं, भावों से होता है। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने गीत पर प्रतिबंध लगाया। विचार करना चाहिए कि यह दो शब्द कितने शक्तिशाली थे, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य डर गया। लेकिन वह भी इसे नहीं रोक पाया। लाखों छात्रों ने अंग्रेज़ों की लाठियां खाईं, माताओं-बहनों ने घर की दहलीज से बाहर निकलकर यह गीत गाया, क्रांतिकारी जेल जाते हुए इसे गुनगुनाते रहे और फांसी पर चढ़ते हुए अंतिम सांस तक यही बोलते रहे-वन्देमातरम्! वन्देमातरम्! उनकी आवाज आज भी इतिहास के पन्नों से निकलकर कानों में गूंजती है। अब यह सिर्फ गीत नहीं रहा, यह बन गया-एक राष्ट्रीय मंत्र, सामूहिक चेतना और भावनात्मक शक्ति का मंत्र।

बंग-भंग आंदोलन से वन्देमातरम् का मंत्र गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ कैलिफोर्निया पहुंच गया। यह मंत्र आजाद हिंद फौज में भी गूंजा। आजाद हिन्द फौज में सैनिक मार्च करते हुए इसे गाते थे। वन्देमातरम् की धुन उनके कदमों में साहस बनकर उतरती थी। इसी तरह यह 1946 में रॉयल इंडियन नेवी की क्रांति में भी वन्देमातरम का नारा गूंजा और भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश युद्धपोतों पर तिरंगा फहराया। खुदीराम बोस से लेकर अशफाक उल्ला खां तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर का तिरुपुर कुमारन तक नारा एक ही था। यह अब केवल एक गीत नहीं रहा बल्कि भारत की सामूहिक आत्मा की आवाज बन गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय आन्दोलन का 'युद्धगीत' कहा।

गांधीजी कहते थे-'वन्देमातरम् तो वह शक्ति है जो हमारी आत्मा को जागृत करती है।' उनकी प्रार्थना सभाओं में भी समय-समय पर इस गीत को गाया जाता था। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लोकमान्य तिलक ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का 'प्रारम्भिक नारा' कहा। अरविंदो घोष ने लिखा-'यह गीत भारतीय राष्ट्र की आत्मा है।' तो बिपिन चंद्र पाल इसे देशभक्ति की धड़कन कहते थे।

वन्देमातरम् गीत में मां सिर्फ मिट्टी नहीं है, मां सिर्फ भूमि नहीं है, मां प्रकृति है, नदी है, धान की बालियां हैं, हवा है, सुगंध है, पहाड़ हैं, फसलें हैं, संस्कृति है। जब कहते हैं-'वन्देमातरम्' तो अर्थ होता है-मां, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मां, मैं तुम्हारे लिए जीता हूं, मां, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूं। भाषा अनेक, बोली अनेक, मत-पंथ अनेक, परंपरा अनेक, वेश, भूषा, खान, पान की विविधता के बावजूद चाहे मराठी हो, बंगाली हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो या गुजराती हो माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः के उस भाव से अभिप्रेत होते हुए उद्घोष करते है वन्देमातरम्।

वन्देमातरम् में अध्यात्म और देशभक्ति का अद्भुत संगम है। वन्देमातरम् केवल देश के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि प्रकृति, धरती, नदी, पहाड़, फसल, सुगंध, वायु सबका वंदन है। जल से सींचने वाली, अन्न देने वाली, हरियाली से जीवन भरने वाली, समृद्धि से पूजित मां के रूप में दिखाई देता है।

भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में यह प्रश्न उठा-क्या भारत का राष्ट्रगान 'वन्देमातरम्' बनेगा? तो कई राजनेता असमंजस में थे। लेकिन सबने इसकी गरिमा को तो स्वीकार किया। परंतु विविधता की भावना का हवाला देते हुए 'जन-गण-मन' राष्ट्रगान चुना गया। वन्देमातरम् को लेकर कई भ्रम पैदा किए गए। देश का एक राजनीतिक दल जो स्वतंत्रता आन्दोलन का बड़ा हिस्सा था, उसने भी इस गीत के साथ अन्याय किया। इसके बाद भी 4 जनवरी, 1950 को भारत की संविधान सभा ने निर्णय दिया और सर्वसम्मति से वन्देमातरम् को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी। यह निर्णय केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं था, इस सत्य का प्रतिपादन भी था कि वन्देमातरम् भारतीय राष्ट्र की एकात्म चेतना, श्रद्धा एवं स्वाभिमान का अमर प्रतीक है। इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि दोनों गीत भारत की आत्मा हैं-एक राष्ट्रगान, दूसरा राष्ट्रगीत।

'वन्देमातरम्' ने जब पहले 50 वर्ष पूरे किए, उस समय देश स्वतन्त्र नहीं था। 100 वर्ष पूरे होने पर देश आपातकाल की बंदिशों में सिमटा हुआ महसूस कर रहा था-तब संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी था। 150 वर्ष पूरे होने पर एक बार फिर से इस महान गीत की प्रेरणादायी यात्रा और उसके महत्व को समझने का अवसर पा रहे हैं। यह निश्चित है कि आज सभी स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं।

लेकिन विचार यह भी करना होगा कि क्या स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्ति है, क्या स्वतंत्रता केवल राजनीतिक है? नहीं स्वतंत्रता का अर्थ स्वार्थ, भ्रष्टाचार, विभाजन, उदासीनता और भय से मुक्ति भी है। वन्देमातरम् यह याद दिलाता है कि सभी का कर्तव्य राष्ट्रनिर्माण में नई ऊर्जा भरना है। यह याद दिलाता है कि सभी उस सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातृ भूमि के संवाहक है, संरक्षक है और यह याद दिलाता है कि भारत एक जन, एक राष्ट्र, एक संस्कृति का वाहक है।

वन्देमातरम् का अर्थ केवल मातृभूमि को प्रणाम करना नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि को यह वचन देना है कि उसकी रक्षा करेंगे, उसे समृद्ध और गौरवान्वित बनाए रखेंगे। जब कोई किसान अपनी भूमि को उपजाता है, सैनिक सीमा पर डटा रहता है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों में संस्कार बोता है और युवा नवाचार से देश का नाम रोशन करता है, तब वन्देमातरम् सही अर्थ में अपने सार्थक रूप में जीवित रहता है।

आज की युवा पीढी को इस गीत के मूल भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तकनीकी के इस युग की तेज रफ्तार के बाद भी प्रत्येक हृदय में मातृ भूमि के प्रति प्रेम और कर्तव्य का संकल्प बना रहे, तभी यह गीत अमर रहेगा। वास्तव में वन्देमातरम् वह गीत है जो भारत को एकात्मकता के सूत्र में पिरोता है। वन्देमातरम् केवल एक गीत नहीं है, यह सामूहिक कर्तव्य की पहचान, राष्ट्रीय गौरव की अभिव्यक्ति और सामूहिक चेतना का साक्षात प्रमाण है। वन्देमातरम् की कहानी केवल इतिहास में बंद पुस्तक नहीं, यह आत्मा में गूंजता शाश्वत सत्य है। ■

(लेखक, अभाविप मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं।)

रचनात्मकता को मिले पंख

युवाओं में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) गोरक्ष प्रांत-बस्ती विभाग द्वारा युवा सृजन एवं नवाचार महोत्सव–2026 का भव्य एवं प्रेरणादायी आयोजन किया गया। यह महोत्सव बस्ती मंडल में युवा प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण आयोजन सिद्ध हुआ, जिसमें बस्ती एवं संत कबीर नगर जनपद से चार सौ से अधिक विद्यार्थियों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

महोत्सव में 90 से अधिक नवाचार आधारित मॉडल प्रस्तुत किए गए। इन मॉडलों में से अधिकांश किसी न किसी सामाजिक, तकनीकी या पर्यावरणीय समस्या के समाधान पर आधारित थे। विद्यार्थियों ने विज्ञान और तकनीक के साथ-साथ ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, जल प्रबंधन, कृषि सुधार, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन तथा समाज जीवन से जुड़ी अनेक चुनौतियों के समाधान को ध्यान में रखते हुए अपने मॉडल तैयार किए। इन नवाचारों ने यह स्पष्ट रूप से दर्शाया कि आज का युवा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अपनी कल्पनाशक्ति और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान खोजने की दिशा में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

महोत्सव में प्रदर्शित मॉडलों की विविधता और गुणवत्ता ने सभी उपस्थित लोगों को प्रभावित किया। कई मॉडल ऐसे थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और कृषि सुधार से संबंधित थे, जबकि कुछ मॉडल ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों तथा पर्यावरण संरक्षण पर आधारित थे। कई विद्यार्थियों ने तकनीकी नवाचारों के माध्यम से दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल बनाने के उपाय प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम में प्रस्तुत सभी नवाचार मॉडलों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक निर्णायक समिति का गठन किया गया था। समिति में आठ निर्णायक शामिल थे, जो विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और नवाचार से जुड़े अपने-अपने विषयों के अनुभवी विशेषज्ञ थे। निर्णायकों ने प्रत्येक मॉडल का गहन अवलोकन करते हुए उसकी वैज्ञानिक अवधारणा, व्यावहारिक उपयोगिता, प्रस्तुतीकरण तथा समाज में उसके संभावित प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया। प्रतिभागियों से उनके मॉडल से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए, जिससे यह समझा जा सके कि उन्होंने अपने नवाचार की अवधारणा को कितनी गहराई से समझा है। विस्तृत और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया के पश्चात कुल 20 उत्कृष्ट नवाचार मॉडलों का चयन किया गया, जिन्हें तीस हजार रुपए की राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डा. विजय कुमार वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में उन्होंने कहा कि भारत का युवा वर्ग अपार प्रतिभा और नवाचार की क्षमता से परिपूर्ण है। यदि युवाओं को सही दिशा और अवसर मिलें, तो वह विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि नवाचार केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान का माध्यम बनना चाहिए।

कार्यक्रम में कई अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार रखे और विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वह अपने विचारों और नवाचारों को व्यवहारिक रूप देकर समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का प्रयास करें। महोत्सव के दौरान विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने न केवल अपने मॉडल प्रस्तुत किए, बल्कि एक-दूसरे के विचारों को समझने और उनसे सीखने का भी प्रयास किया। समापन अवसर पर युवाओं में नवाचार, वैज्ञानिक चेतना और राष्ट्र निर्माण की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया गया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

उत्तर-पूर्व में कृषि के भविष्य पर मंथन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के आयाम एग्रीविजन ने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल एवं अंतर-राज्य छात्र जीवन दर्शन (सील) के सहयोग से इंफाल में तीन दिवसीय एग्री यूथ पार्लियामेंट–2026 का सफल आयोजन किया। उत्तर-पूर्व भारत में कृषि का भविष्य : सतत विकास, नवाचार और अवसर (फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर फॉर नॉर्थ ईस्ट भारत : सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशंस एंड अपॉर्च्युनिटीज) विषय पर आधारित एग्री यूथ पार्लियामेंट–2026 का उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, उद्यमियों और उद्योग विशेषज्ञों को एक ऐसा साझा मंच प्रदान करना रहा, जहां पूर्वोत्तर भारत में कृषि के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

गत 21 से 23 मार्च के मध्य आयोजित एग्री यूथ पार्लियामेंट-2026 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने अपने संबोधन में पूर्वोत्तर भारत को जैविक कृषि का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए युवाओं से नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (इंफाल) के कुलगुरु डा. अनुपम मिश्र, असम कृषि विश्वविद्यालय (जोरहाट) के कुलगुरु डा. दीपज्योति राजखोवा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (इंफाल) के अधिष्ठाता प्रा. के. नंदिनी देवी, अभाविप उत्तर-पूर्व के क्षेत्रीय संगठन मंत्री कमल नयन, राष्ट्रीय मंत्री कमलेश सिंह, एग्रीविजन के राष्ट्रीय संयोजक मनीष फटे, आयोजन सचिव प्रा. इंदिरा सरंगथेम, संयोजक रोशनी शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

32 प्रदर्शनी और स्टार्टअप शो-केस बने आकर्षण

तीन दिवसीय कार्यक्रम में 32 प्रदर्शनी और स्टार्टअप शो-केस आयोजित किए गए। तीन अन्य तकनीकी सत्रों में आधुनिक कृषि के विभिन्न आयामों पर गहन चर्चा हुई। पहले सत्र में एग्री-स्टार्टअप और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक उपयोग, जनजातीय समाज की भागीदारी और पारंपरिक खेती से हटकर कृषि क्षेत्र में नवीन विचारों, तकनीकों और व्यापारिक मॉडल जैसे विषय शामिल रहे। प्रदर्शनी के दौरान महिला नेतृत्व में केले के रेशे से पर्यावरण अनुकूल कपड़ा बनाने की पहल

विशेष आकर्षण का विषय रही। दूसरे सत्र में कृषि और सहायक क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अत्याधुनिक बागवानी, डेयरी क्षेत्र में उन्नत प्रजनन तकनीक, पर्ल कल्चर, ब्लू इकोनॉमी और एक्वाप्रेन्योरशिप के अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया।

एग्री यूथ पार्लियामेंट-2026 के तीसरे सत्र में फार्म-टू-मार्केट सिस्टम, वैल्यू चेन और बाजार-आधारित कृषि क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों के उपयोग, एग्रीबिजनेस मॉडल और कृषि अपशिष्ट के उपयोग से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में गहन विचार किया गया। कृषि क्षेत्र को भविष्य की दृष्टि से आधुनिक बनाने की दृष्टि से आयोजित इन सत्रों में अठारह विषय विशेषज्ञ, छह अध्यक्ष, छह विशेषज्ञ और बारह प्रतिवेदक सहित कई अन्य प्रगतिशील उद्यमियों और उत्साही छात्रों ने हिस्सा लिया।

600 से अधिक प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी

एग्री यूथ पार्लियामेंट-2026 कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों-असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगभग 400 छात्र, 30 प्राध्यापक और 200 कार्यकर्ताओं सहित 600 से अधिक लोगों की भागीदारी रही। तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने 70 से अधिक मौखिक एवं पोस्टर प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने शोध और नवाचार प्रस्तुत किए।

समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

एग्री यूथ पार्लियामेंट-2026 के समापन अवसर पर गत 23 मार्च को कालेज ऑफ एग्रीकल्चर (इंफाल) में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने हिस्सा लिया। समापन सत्र में एग्रीविजन के राष्ट्रीय प्रमुख विक्रम फर्स्वान, डा. अनुपम मिश्रा (कुलगुरु, केंद्रीय कृषि विवि, इंफाल), डा. प्रभा शंकर शुक्ल (कुलगुरु, एनईएचयू, शिलांग), कमल नयन (क्षेत्रीय संगठन मंत्री, अभाविप), डा. अमित गोस्वामी (राष्ट्रीय सलाहकार परिषद सदस्य, एग्रीविजन), प्रा. इंदिरा सारंगथेम तथा डा. जेती कोंसम भी उपस्थित रहे। समापन सत्र में एग्री यूथ पार्लियामेंट के प्रमुख निष्कर्षों-छात्र-नेतृत्व वाले नीति सुझाव, नवाचार संबंधी समाधान और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया। समग्र रूप से 'एग्री यूथ पार्लियामेंट-2026' एक ऐसे सशक्त मंच के रूप में सामने आया, जहां सहयोग, नवाचार और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही यह सन्देश भी दिया गया कि युवा शक्ति ही सतत कृषि विकास, उद्यमिता और भविष्य के लिए सक्षम कृषि प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

नवाचार और उद्यमिता पर मंथन

'सविष्कार' का दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन 'सविष्कार स्टार्टअप संगम 2026' लखनऊ स्थित डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू), लखनऊ में सम्पन्न हुआ। नवाचार और उद्यमिता के इस दो दिवसीय महाकुंभ में युवाओं को अपने विचारों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रेरित किया गया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के प्रकल्प 'सविष्कार' का दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन 'सविष्कार स्टार्टअप संगम-2026' का शुभारम्भ गत 28 फरवरी को एकेटीयू में हुआ था। नवाचार और उद्यमिता के इस महाकुंभ के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अभय प्रताप सिंह उपस्थित रहे। अपने सम्बोधन में मुख्य अतिथि ए. के. शर्मा ने कहा कि आज देश का युवा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी विश्व की अग्रणी कंपनियों का नेतृत्व कर रहा है,लेकिन प्रश्न यह है कि वह भारत में रहकर 'गूगल' क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हमारा सामाजिक परिवेश है, जो नए प्रयोगों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं देता। इस मानसिकता की जंजीरों को तोड़ना होगा। यदि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो युवाओं को उनके स्टार्टअप और नवाचार के सपनों में सहयोग देना होगा।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अभय प्रताप सिंह ने कहा कि सविष्कार के माध्यम से अभाविप युवाओं को 'जॉब सीकर' से 'जॉब क्रिएटर' बनाने का प्रयास कर रही है। उद्घाटन समारोह में सविष्कार के राष्ट्रीय संयोजक निसर्ग राठौड़, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. दीपक नगरिया तथा लोक नीति भारत के निदेशक सत्येंद्र त्रिपाठी सहित कई अन्य अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए।

दो दिवसीय सम्मेलन में नौ तकनीकी सत्रों के माध्यम से प्रतिनिधियों को उद्यमिता के क्षेत्र में सक्रिय योगदान के लिए प्रेरित किया गया। स्टार्टअप सम्मेलन में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों ने पैनल संवाद में हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों के लिए 'भजन क्लबिंग' और 'ओपन माइक' जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

सम्मेलन के समापन समारोह में अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री देवदत्त जोशी ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जोशी ने कहा कि भारतीय युवा अब केवल नौकरी की कतार में खड़ा रहने वाला नहीं, बल्कि समाज को नई दिशा और रोजगार देने वाला बन रहा है। सविष्कार जैसे मंचों से निकलने वाले स्टार्टअप्स का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि उनका मूल लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की समस्याओं का समाधान खोजना है। यही सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण है।

अपने सम्बोधन में अभाविप पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही ने बताया कि दो दिवसीय संगम में देशभर से आए लगभग 250 प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। छोटे नगरों और ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों के पास भी अत्यंत व्यावहारिक और परिवर्तनकारी स्टार्टअप आइडिया हैं। अभाविप और सविष्कार का यह संयुक्त प्रयास इन विचारों को कागजों से निकालकर धरातल पर उतारने का एक अनुष्ठान है। सविष्कार के राष्ट्रीय संयोजक निसर्ग राठौड़ के अनुसार 'सविष्कार स्टार्टअप संगम-2026' केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक वैचारिक क्रांति का आरम्भ है। यहां से निकलने वाला हर युवा भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

A Grand Celebration of Young Filmmakers and Cinematic Innovation

The National Students' Film Festival-2026 (NSFF-2026) concluded successfully after a vibrant two-day event held on February 28 and March 1 at the University of Mumbai, Kalina Campus. The festival was jointly organized by Rashtriya Kala Manch (RKM), Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) and Vidyarthi Nidhi Trust, drawing enthusiastic participation from young filmmakers across the country.

The festival featured screenings of films in multiple languages, along with guidance sessions and thought-provoking discussions, making it an inspiring platform for emerging cinematic talent. Renowned film director Ravi Udyawar inaugurated the event. Following the inauguration, a jury briefing session was held with eminent personalities from the film industry. Writer Nidhi Singh Dharma, film writer Amarnath Jha, music director Rahul Suhas, National Award-winning director Neeraj Kumar Mishra, film editor Vandita Chakradeo and director Vishal Chaturvedi guided participants. They shared valuable insights on the evolving media landscape, the changing dynamics of cinema and the social responsibility of filmmakers, encouraging students to pursue innovation and meaningful storytelling.

A total of 30 films were shortlisted and screened during the festival, representing a wide range of themes, genres and languages. The screenings received an enthusiastic response from audiences. Additionally, four masterclasses were conducted by industry experts. Abhijeet Deshpande spoke on storytelling and screenplay writing, Sudip Lahiri discussed emerging technologies in filmmaking, Kedar Gaikwad delivered sessions on cinematography, editing and sound and V. N. Aditya shared perspectives on film ethics and the future of cinema. Satyajit Mandle, Deputy Director of the National Museum of Indian Cinema, also attended the festival and conducted a networking session, offering guidance and practical insights into building a career in cinema. A special panel discussion on 'AI and the Future of Indian Cinema' featured filmmaker Pooja Kadam and producer Avinash Tripathi, who explored the growing influence of artificial intelligence in filmmaking and its potential impact on the industry.

The festival concluded with a grand valedictory ceremony attended by several distinguished guests, including Maharshi Shah, Creative Director of Birla Studios, who served as the chief guest. Other notable attendees included ABVP National Organisation Secretary Ashish Chauhan, Chairman of Film Development Authority Tarun Rathi, RKM National In-charge Ankit Shukla and University of Mumbai's Director of Student Welfare, Sunil Patil.

The award ceremony marked a highlight of the event. **Panpankh** won the Best Film Award, while **Songti and Seize** received special appreciation. **Saanjha Kuan** was awarded Best Music, **Riha** won Best Editing, **Baap Re Baap** received the Best Young Director Award and The Queue was honored as the Best Promising Voice.

Maharshi Shah emphasized the importance of learning from the rich heritage of Indian cinema to develop a unique creative voice. Ankit Shukla highlighted RKM's 'Triple P Concept' -Passion, Platform and Purpose as a guiding principle for artists. Tarun Rathi underscored the importance of originality in cinema through unique concepts, characters and scenes, while Ashish Chauhan stressed the need for perseverance in artistic pursuits. ■

(Rashtiya Chhatrashakti Team)

नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता का भव्य प्रदर्शन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) एवं सृजन संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित डिपेक्स (डिप्लोमा, डिग्री एवं आईटीआई प्रोजेक्ट प्रदर्शनी)-2026 में अबकी बार रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई। 450 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा कठोर मूल्यांकन के पश्चात 389 परियोजनाओं का चयन अंतिम रूप से किया गया, जिनमें 1,412 प्रतिभागियों ने अपने कार्यशील मॉडल प्रस्तुत किए। डिपेक्स-2026 में कृषि प्रौद्योगिकी, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, ऊर्जा एवं सतत विकास, औद्योगिक स्वचालन, स्वास्थ्य तकनीकी, साइबर सुरक्षा, गतिशीलता, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अपशिष्ट प्रबंधन जैसे समकालीन विषयों पर आधारित परियोजनाएं सामने आईं। यह सभी क्षेत्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं-सतत विकास, डिजिटल परिवर्तन और आत्मनिर्भरता-के अनुरूप हैं।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईटी) परिसर में डिपेक्स-2026 का आयोजन गत 5 मार्च से लेकर 8 मार्च के मध्य किया गया। डिपेक्स श्रृंखला के इस 35वें आयोजन ने इंजीनियरिंग, कृषि एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में छात्र नवाचार के लिए राज्यस्तरीय मंच प्रदान किया। उद्घाटन समारोह में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डा. एस. सोमनाथ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स-नागपुर) के अध्यक्ष डा. अनंत पांढरे तथा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अतुल सावे सहित अन्य कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। समारोह में अभाविप, एमआईटी के पदाधिकारी, उद्योग जगत और शैक्षणिक क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

चार दिवसीय कार्यक्रम के दौरान भारत क्वांटम मिशन, स्टार्टअप इनक्यूबेशन, वित्तीय समावेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं सेमीकंडक्टर जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र और चर्चाओं के साथ ही छात्रों के समग्र विकास एवं संतुलित डिजिटल व्यवहार पर भी सत्रों का आयोजन किया गया। डिपेक्स-2026 में नवाचार और इनक्यूबेशन पर विशेष जोर रहा। कार्यक्रम में 17 इनक्यूबेशन केंद्रों के 38 प्रतिनिधियों ने छात्रों से संवाद किया, जिसमें 156 परियोजनाओं को इनक्यूबेशन सहायता के लिए चयनित किया गया। प्रत्येक चयनित टीम को बौद्धिक संपदा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पांच हजार रुपए के पेटेंट सहायता वाउचर प्रदान किए गए।

डिपेक्स-2026 में 110 से अधिक विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। विभिन्न श्रेणियों में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कारों के साथ-साथ 'बेस्ट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट', 'वुमन इन टेक्नोलॉजी' और 'एमएसबीटीई पुरस्कार' जैसे विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए गए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक (पुणे) को समग्र विजेता घोषित किया गया। कार्यक्रम में कुल 63 पुरस्कार एवं चार विशेष सम्मान वितरित किए गए। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय (महाराष्ट्र) के वरिष्ठ अधिकारियों सहित शिक्षा, शासन एवं उद्योग जगत के गणमान्य व्यक्ति उपस्थिति रहे। डिपेक्स-2026 में पच्चीस हजार से अधिक छात्रों, शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों एवं नीति-निर्माताओं ने हिस्सा लिया। वास्तव में डिपेक्स-2026 ने पुनः नवाचार को प्रोत्साहित करने, शिक्षा और उद्योग के मध्य सेतु स्थापित करने तथा युवाओं को तकनीक और अनुसंधान के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित करने में अपनी भूमिका को सशक्त रूप से सिद्ध किया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

पाठ्यक्रम से हटेंगे जिन्ना-इकबाल

अभाविप के विरोध के बाद लिया गया पाठ्यक्रम बदलने का निर्णय

जम्मू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर (एमए) राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल से संबंधित विषयों को हटाने की सिफारिश की गई है। यह निर्णय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के विरोध-प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित समीक्षा समिति ने लिया। इससे पहले अभाविप ने जिन्ना पर आधारित अध्याय को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।

जम्मू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बलजीत सिंह मान के अनुसार गत 22 मार्च को फैकल्टी और विभागीय मामलों की समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एक वर्षीय और दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल से जुड़े विषयों को हटा दिए जाएं। अध्यायों को हटाए जाने सम्बन्धी निर्णय को विचार के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज को भेजा गया है। इससे पूर्व विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम का बचाव करते हुए कहा था कि जिन्ना और अन्य विचारकों को शामिल करना पूरी तरह से शैक्षणिक उद्देश्य के लिए और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

जम्मू विश्वविद्यालय में विवाद की स्थिति तब बनी, जब राजनीति शास्त्र विभाग ने 2026-2028 का पाठ्यक्रम जारी किया। इसमें 'आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार' पाठ्यक्रम के अंतर्गत जिन लोगों को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि बताया गया, उनमें सर सैयद अहमद खान, मुहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल के नाम भी शामिल किए गए। पाठ्यक्रम जारी होने के बाद उत्पन्न हुए विवाद के बीच अभाविप ने विरोध करते हुए कहा कि यह वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने देश के विभाजन में भूमिका निभाई और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का प्रचार किया। इनके विषय में पढ़ाया जाना चिंता का विषय है।

विरोध के बाद अभाविप ने मांग की कि विभाजन और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत से जुड़े चेहरों के बारे में पढ़ाना छात्रों को स्वीकार्य नहीं है। इसके स्थान पर उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सकारात्मक कार्य किए हैं। अपनी मांग को लेकर अभाविप ने लगातार जम्मू विश्वविद्यालय में विरोध-प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम पाठ्यक्रम से अध्याय को हटाए जाने के निर्णय के रूप में सामने आया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

जीवंत हुए 'प्रिय केलकर'

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के शिल्पकार प्राध्यापक यशवंत राव केलकर की जन्मशताब्दी के अवसर पर उदयपुर एवं जोधपुर में 'प्रिय केलकर' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षाविदों एवं अभाविप कार्यकर्ताओं की उपस्थित में हुए कार्यक्रमों में प्रा. केलकर का स्मरण किया गया। साथ ही उनके जीवन, संगठन निर्माण में भूमिका, अभाविप की कार्यशैली तथा युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका सम्बन्धी विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

उदयपुर में अभाविप चितौड़ प्रांत द्वारा गत 9 मार्च को आयोजित 'प्रिय केलकर' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संयोजक (पर्यावरण संरक्षण गतिविधि) गोपाल आर्य उपस्थित रहे। प्रा. केलकर के विचारों, उनके व्यक्तित्व तथा अभाविप के संगठन निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि उनके आदर्श और कार्यपद्धति आज भी अभाविप कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री देवदत्त जोशी ने वर्तमान समय में युवाओं के सामने उत्पन्न हुई डिजिटल चुनौती पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण युवाओं की एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभाविप अपने विभिन्न आयामों और गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी पूर्ण क्षमता पहचानने और उसे विकसित करने के लिए प्रेरित कर रही है, ताकि वह राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

कार्यक्रम में पुणे से आई अभिवाचन टोली ने दृश्य-श्रव्य माध्यम से यशवंत राव केलकर के जीवन-वृत्त का प्रभावशाली अभिवाचन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अभाविप उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा, अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा, प्रांत मंत्री जितेंद्र लोधा, प्रांत अध्यक्ष पारस टाक तथा प्रांत संगठन मंत्री वीरेंद्र सिंह शक्तावत सहित बड़ी संख्या में अभाविप कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उधर **जोधपुर** प्रान्त द्वारा आयोजित 'प्रिय केलकर' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा उपस्थित रहे। काजरी स्थित अंतरराष्ट्रीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रा. केलकर केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि राष्ट्र चिंतक, संगठन शिल्पी और विचारों से प्रेरित नेतृत्वकर्ता थे। उनका मानना था कि विद्यार्थी जीवन में संगठन के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र चिंतन की दिशा मिलती है और अभाविप ऐसे सुयोग्य नागरिक तैयार करती है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुचिता और नैतिकता का पालन करते हैं।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जीवन में अभाविप के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि आज अभाविप की जो पहचान और ख्याति है, वह असंख्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है। प्रा. केलकर का स्मरण करते हुए उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा ने कहा कि अभाविप ने सदैव छात्र शक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए संगठित करने का कार्य किया है। कार्यक्रम में जोधपुर प्रांत भर से बड़ी संख्या में पूर्व कार्यकर्ता, वर्तमान कार्यकर्ता और प्राध्यापक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्लुएंस-2026

नैतिकता, पारदर्शिता एवं मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विविध पक्षों पर चिंतन

विश्व छात्र एवं युवा संगठन (डब्लूओएसवाई), मेटा एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय 'ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्लुएंस-2026' कार्यक्रम का आयोजन गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विदेशी मूल के 180 विद्यार्थी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश, गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन, डब्लूओएसवाई के चेयरपर्सन डा. नितिन शर्मा तथा लीला उपस्थित रहीं।

अपने उद्घाटन सम्बोधन में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्लुएंस-2026 केवल एक तकनीकी आयोजन नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर विचारों के मंथन का एक सशक्त मंच है, जहां 26 देशों के प्रतिभागी 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना को साकार कर रहे हैं। उन्होंने शोधार्थियों से आह्वान किया कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में कार्य करते हुए मानवता के हित और नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की चर्चा करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि ज्ञान और समाज की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति बनती जा रही है। यह आवश्यक है कि केवल उपभोक्ता न बनकर अपनी भाषाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप एआई मॉडल विकसित करें, अन्यथा वैश्विक शक्तियों का डाटा पर एकाधिकार हो जाएगा। उन्होंने एलन मस्क जैसे विशेषज्ञों की चिंताओं का उल्लेख करते हुए एआई के विकास में नैतिकता, पारदर्शिता और मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रखने पर जोर दिया।

अपने सम्बोधन में आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने मानव बुद्धिमत्ता को सदैव एआई से ऊपर रखने पर जोर देते हुए कहा कि यह तकनीक तभी सार्थक है, जब वह आपातकालीन चिकित्सा और कृषि जैसे क्षेत्रों में जीवन को सरल और सुरक्षित बनाए। एआई डाटा का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय और जिम्मेदारी सदैव मानव की होनी चाहिए।

गत 27 एवं 28 मार्च को आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में छह सत्रों का आयोजन किया गया। पहले दिन उद्घाटन सत्र के बाद विजन डिजिटल इंडिया के तत्वावधान में एआई स्टार्टअप विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। दूसरे दिन 'एक सुलभ भविष्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता', 'एआई के युग में संस्कृति एवं शिक्षा', 'उद्यमिता एवं एआई' विषयों पर आयोजित सत्रों के साथ चार सत्रों में एआई के सकारात्मकता के साथ नकारात्मकता पर गहन चर्चा की गई। दो दिवसीय कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान परिदृश्य, इसके तीव्र विस्तार, वैश्विक प्रभाव तथा भविष्य की असीम संभावनाओं पर गहन मंथन किया गया। साथ ही एआई के नवाचार, उभरती तकनीकों, शोध की नई दिशाओं तथा समाज एवं शिक्षा के क्षेत्र में इसके प्रभावी उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।

कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल के नव निर्वाचित सांसद संदीप राणा, अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री बालकृष्ण, डब्लूओएसवाई के चेयरपर्सन डा. नितिन शर्मा और महामंत्री शुभम गोयल उपस्थित रहे। समापन समारोह

में 26 देशों से आए विद्यार्थियों ने अपने-अपने देशों की संस्कृति का प्रदर्शन लोक नृत्य के माध्यम से किया।

समापन सत्र में अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बालकृष्ण ने कहा कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है, जिससे विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही भ्रामक जानकारी, डाटा गोपनीयता, तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता और रोजगार के बदलते स्वरूप जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि वह एआई का उपयोग जागरूकता, नैतिकता और आलोचनात्मक सोच के साथ करें तथा अपने ज्ञान, संस्कार और रचनात्मकता को सशक्त बनाएं।

कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए डब्लूओएसवाई के अध्यक्ष नितिन शर्मा ने कहा कि 'ग्लोबल एआई कॉन्फ्लुएंस-2026' जैसे मंच युवाओं को नवाचार, तकनीक और वैश्विक दृष्टिकोण से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज विश्व को नई दिशा दे रही है और ऐसे में विद्यार्थियों एवं युवा उद्यमियों के लिए यह आवश्यक है कि वह इस तकनीक को सीखें, समझें और समाजहित में उसका उपयोग करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कॉन्फ्लुएंस प्रतिभागियों के ज्ञान, कौशल और नेतृत्व क्षमता को सशक्त करेगा तथा उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। राजस्थान ।

महापुरुषों का अपमान करने वालों के विरुद्ध होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई : अभाविप

भारत के गौरवपूर्ण इतिहास, महत्वपूर्ण अभिलेखों तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जनसामान्य और विद्यार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में लगाई गई विशेष प्रदर्शनी में कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध एवं तोड़फोड़ की घटना की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने कड़ी निंदा की है। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अभाविप ने कहा है कि यह केवल संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अभाविप ने घटना में लिप्त तत्वों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

जानकारी हो कि केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित संस्था राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा भारत की विश्व विरासत-राजस्थान विषयक नाम से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में किया गया। इसमें राजस्थान के ऐतिहासिक दस्तावेजों, महत्वपूर्ण अभिलेखों तथा देश एवं राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं आम लोगों को अपने इतिहास और विरासत से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना था। अभाविप ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे भारत की ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा।

बाद में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गत 15 मार्च को न केवल प्रदर्शनी में तोड़ फोड़ की, बल्कि राजस्थान के शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप, मीरा बाई की तस्वीरों को कुचलकर महापुरुषों का अपमान किया। विरोध कर रहे तत्वों ने प्रदर्शनी के द्वार को तोड़कर नीचे गिरा दिया। अभाविप ने घटना की कड़ी निंदा की है। अभाविप जोधपुर प्रांत मंत्री दशरथ गर्ग के अनुसार एनएसयूआई ने महापुरुषों का नहीं, एक परिवार का सम्मान करना ही सीखा है, एक परिवार की दासता ने इनको मानसिक रूप से बंधुआ मज़दूर बना दिया है। यह देश के सम्मान और महापुरुषों के सम्मान की बात कभी नहीं कर सकते हैं। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

गोरखपुर : ग्लोबल एआई कॉन्फ्लुएंस-2026 का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, आईआईटी भिलाई निदेशक प्रा. राजीव प्रकाश, गोरखपुर विवि कुलगुरु प्रा. पुनम टंडन, विश्व छात्र युवा संगठन के चेयरपर्सन डा. नितिन शर्मा एवं केंद्रीय कार्यकारी परिषद की सदस्य ऐला।

गोरखपुर : ग्लोबल एआई कॉन्फ्लुएंस में उपस्थित प्रतिभागी एवं अतिथिगण।

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 APRIL, 2026
DATE OF PUBLISHING: 8 APRIL, 2026

POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26

राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म महोत्सव-2026

मुंबई : राष्ट्रीय कला मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करते हुए फिल्म निर्देशक रवि उद्यावर, विज्ञापन निर्माता राज कांबले, अभाविप राष्ट्रीय मंत्री पायल किनाके एवं राष्ट्रीय कला मंच संयोजक अभिनव दीप।

मुंबई : राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म विजेता को पुरस्कृत करते हुए फिल्म निर्माता महर्ष शाह, तरुण राठी, मुंबई विवि छात्र कल्याण अधिष्ठाता सुनील पाटिल, अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय कला मंच प्रमुख अंकित शुक्ल, महोत्सव संयोजक सौम्या चवरे एवं अन्य।